● वर्ष-2
● अंक-220
रायपुर, शनिवार
06 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाकिस्तान -जयशंकर

एससीओ बैठक में विदेश मंत्री का बड़ा हमला, चीन सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं

पणजी । शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान को साफ तौर पर आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता घट रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिलावल के साथ बाकी के विदेश मंत्रियों की ही तरह बर्ताव हुआ। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए आतंकवाद के अपराधियों के साथ एक साथ नहीं बैठते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए थे।

जयशंकर ने पाक विदेश मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और पोषण करने वाले साथ नहीं बैठ सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जी-20 की बैठकें हो रही हैं, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।

विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के जी-20 और श्रीनगर मुद्दा है ही नहीं पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ पीओके ही मुद्दा है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर में जी-20 की बैठक होगी।

आपको बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जी-20 की बैठक को लेकर लगातार आपत्ति जता रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जी-20 और श्रीनगर से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ केवल पीओके बड़ा मुद्दा है। चीन को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर असामान्य स्थिति है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीमा पर हालात सुधरने तक चीन के साथ सामान्य स्थिति नहीं है। चीन से डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्री छिन कांग ने दोहराया था कि भारत-चीन सीमा पर स्थिति सामान्यतः स्थिर है और दोनों पक्षों को मौजूदा प्रयासों को मजबूत करना चाहिए तथा सीमा पर स्थायी शांति के लिए शर्तों को और सरल एवं सहज बनाने पर जोर देते हुए संबंधित समझौतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

आपसी सहयोग और सुरक्षा पर बात

गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि आपसी सहयोग और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। एससीओ देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि रूस के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। रूस के साथ आर्थिक सहयोग पर भी बात हुई है। चीन को लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन से एलएसी के वर्तमान हालात को लेकर बातचीत हुई है।

जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान, एससीओ के विदेश मंत्रियों ने उन निर्णयों की स्थिति का आकलन किया जिन्हें जुलाई में आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में अनुमोदित किया जाएगा। बैठक ने हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एससीओ में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति पर विचार करने का अवसर भी दिया। उन्होंने कहा कि बैठक ने संगठन के सुधार और आधुनिकीकरण के बारे में बात करने और नए सदस्य राज्यों के रूप में ईरान और बेलारूस को एससीओ में शामिल करने की प्रगति का आकलन करने का अवसर दिया। गोवा में विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद के मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि हमने कई क्षेत्रीय, वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

राजनयिक स्कोरिंग के लिए आतंकवाद हथियार न बनें- बिलावल

विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने एससीओ परिषद को संबोधित करते हुए सदस्य देशों से एक राजनयिक उपकरण के रूप में आतंकवाद का उपयोग करने से बचने का आग्रह किया। अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन बोलते हुए, विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने में एससीओ देशों के बीच अधिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया, इस मुद्दे के मूल कारणों को दूर करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया। हमारे लोगों की सामूहिक सुरक्षा हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। विदेश कार्यालय (एफओ) ने बिलावल के हवाले से कहा, राजनयिक बिंदु स्कोरिंग के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने में न फंसें। बता दें कि करीब 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले साल 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत का दौरा किया था।

इन दिनों ✍ रविशंकर रवि

मणिपुर : राख के नीचे सुलग रही पुरानी आग

मणिपुर एक फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। घाटी से पहाड़ तक हिंसा फैल चुकी है। मैतेई और पहाड़ी जिले के आदिवासी एक-दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। पहाड़ी जिले में जहां मैतेई समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं, वहीं इंफाल समेत मणिपुर के मैदानी इलाकों में पहाड़ी जिलों से आकर बसे आदिवासियों पर मैतेई हमले कर रहे हैं। स्थिति विषम बनी हुई है। सेना और अर्द्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण है। देखते ही गोली मारने के आदेश के बावजूद इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। दरअसल, यह पुरानी आग है, जो बुझी नहीं थी, राख के नीचे गर्म थी। पहाड़ी जिले में बसे मैतेई एसटी (अनुसूचित जनजाति) का दर्जा मांग रहे हैं, जबकि पहाड़ी जिले के आदिवासी इसके लिए कतई तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिलते ही एसटी को मिलने वाली सारी सुविधाओं पर मैतेई का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है और बौद्धिक रूप से वे ज्यादा समर्थ हैं। पहाड़ी जिले में बसे मैतेई को एसटी का दर्जा देने के मणिपुर उच्च न्यायालय के गत 19 अप्रैल के निर्देश के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स मणिपुर ने गत मंगलवार को पहाड़ी जिले चुराचांदपुर में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। तब तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की। उसके बाद स्थिति विस्फोटक हो गई। मणिपुर सरकार स्थिति का पूर्व आकलन करने में चूक गई। हालांकि केंद्र सरकार स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल भेज चुकी है। इसमें दो राय नहीं है कि मैतेई घाटी में रहते हैं और वे बहुसंख्यक हैं। लेकिन जिनकी आबादी कम है, उनके भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्हें छठी अनुसूची का दर्जा चाहिए ताकि बाहर से आए लोगों को वहां पर स्थानीय लोगों की तरह अधिकार न मिले। यह कहना उचित नहीं है कि मैतेई हिंदू हैं तो पहाड़ी जिले के आदिवासियों का अधिकार छीन लिया जाए। पहाड़ी जिलों में 40 फीसदी आबादी ईसाई है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों को ग्रेटर नगालैंड में शामिल करने की मांग होती रही है। मैतेई समुदाय के वर्चस्व से बचने के लिए मणिपुर के पहाड़ी जिले के अधिकांश लोग ग्रेटर नगालैंड में शामिल होने को तैयार हैं। उन्हें मणिपुर में रखने के लिए मणिपुर सरकार को उनकी चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखनी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि राज्य सरकार मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तत्काल उच्चतम न्यायालय में अपील करे और पहाड़ी जिलों के लोगों के लिए छठी अनुसूची का प्रावधान रखे। तभी पहाड़ी जिलों के लोगों को मणिपुर में रखा जा सकेगा और उनका विश्वास पाया जा सकेगा।

कश्मीरी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए तमाम नये बिजनेस आइडियाज लेकर आ रही हैं और सफल भी हो रही हैं। इसी कड़ी में आज की रिपोर्ट में आपको मिलवाते हैं श्रीनगर की अंजुम से जिनकी कपड़े की दुकान आजकल खूब लोकप्रिय हो रही है क्योंकि उनकी दुकान में विभिन्न प्रकार के कपड़े या पर्दे मीटर अथवा संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकते हैं।

समिति की मंजूरी नहीं, पवार ने इस्तीफा वापस लिया

■ **कहा- कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता**

मुंबई। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूं। मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। पवार ने कहा कि आपके प्यार की वजह से मुझसे इस्तीफा वापस लेने की मांग और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का मैं सम्मान कर रहा हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का अपना फैसला वापस लेता हूं।

पवार से कहा कि राकांपा के लिए नए उत्साह के साथ काम करूंगा। राकांपा में उत्तराधिकार की योजना बनानी होगी। पार्टी में सांगठनिक बदलाव पर ध्यान देंगे। बता दें कि राकांपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के बाद दो मई को पवार ने पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसमें उनके भतीजे अजित पवार, पुत्री सुप्रिया सुले, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शामिल थे।

जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए और समय मांगा है। राकांपा का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित की गई समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने के शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया था।

अजित पवार नहीं रहे मौजूद

शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके भतीजे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार मौजूद नहीं रहे। इसको लेकर अटकले शुरू हो गई हैं। एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार उनसे इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करने के लिए वहां मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में निर्णय लिए जाने के बाद जब हम पवार साहब के आवास पर गए तब भी वह वहीं थे।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां तक कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता नहीं था, मैं थोड़ी देर से पहुंचा। सभी को नहीं बताया गया था। आपको बता दें कि अजित पवार ने शरद पवार के इस्तीफे का समर्थन किया है। अजित पवार की अनुपस्थिति के बारे में शरद पवार से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई मौजूद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अन्य यहाँ हैं। कमेटी ने यह फैसला लिया और उनके फैसले के बाद मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। सभी एकजुट हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। समिति में वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और मुझे इससे अवगत कराया।

प्रमुख समाचार

आतंकियों से मुठभेड़ में पांच जवान शहीद, ऑपरेशन जारी

राजोरी। जम्मू संभाग के जिला राजोरी के कंडी इलाके में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। इस घटना के बारे में सेना ने बयान जारी कर बताया कि एनकाउंटर के दौरान दो जवान शहीद हो गए हैं। जबकि, एक अधिकारी समेत चार घायल हैं। आतंकियों के भी ढेर होने की संभावना है। वहीं, घायल जवानों को कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया गया है। इनमें से तीन जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया।

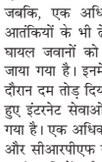

बिहार में जातिगत जनगणना होकर रहेगा : लालू यादव

पटना। बिहार में जातीय गणना पर रोक हाईकोर्ट की ओर से लगा दी गयी। जिसके बाद सरकार की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दे दिया गया कि जातिगत जनगणना के दूसरे फेज के काम को फौरन रोक दिया जाए। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह हो कर रहेगा। वहीं भाजपा पर भी लालू यादव ने हमला बोला और सवाल किए कि भाजपा बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? लालू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच-नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए आरजेडी प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश की जनता जातिगत जनगणना पर भाजपा की

ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री पढ़ेंगे बाइबिल के कुछ अंश

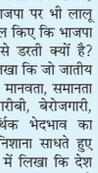

लंदन। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की शपथ के साथ ही पहली बार कोई हिंदू प्रधानमंत्री बना। 6 मई को वहां किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में ऋषि सुनक एक प्रमुख अतिथि के रूप में शरीक होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक देश के हालिया परंपरा को ध्यान में रखते हुए वेस्टमिंस्टर अबे में राज्याभिषेक समारोह में 'बिब्लिकल बुक ऑफ कोलोसियन' के कुछ अंश पढ़ेंगे। यह जानकारी आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी के कार्यालय की ओर से दी गई। सुनक ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं और हिंदू धर्म मानते हैं। ऐसे में ईसाई समारोह में ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तक के अंश पढ़ना बहु-आस्था विषय को प्रतिबिंबित करेगा। कैंटरबरी के आर्चबिशप के कार्यालय 'लैम्बेथ पैलेस' की ओर से कहा गया कि अन्य आस्था के सदस्य पहली बार एक सामूहिक प्रार्थना में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ऋषि सुनक बाइबिल पढ़कर ईसाई समारोह की बहु विश्वास को आगे बढ़ाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बैस्टिल डे के अतिथि होंगे

नई दिल्ली। भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को पेरिस में सम्मानित अतिथि के रूप में इस वर्ष के बैस्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए, एक भारतीय सशस्त्र बल अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में भाग लेंगे। राष्ट्रपति ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ के साथ जोड़ा जाएगा और एक भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी फ्रांसीसी सेना के साथ परेड में भाग लेगी। यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे समय की बड़ी चुनौतियों, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त पहल करने की भी अनुमति देगी।

डीआरडीओ के वैज्ञानिक को एटीएस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट भारत में बैठे बैठे खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रदीप कुरूलकर के तौर पर हुई है जिस पर पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। पाकिस्तान को उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारियां मुहैया कराई है। इस संबंध में एटीएस के एक अधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक कथित तौर पर व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के माध्यम से पाकिस्तान खुफिया कर्मियों के एक एजेंट के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि यह 'मोहपाश में फंसाने' का मामला है। आरोपी रक्षा अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ पद पर रह चुका है और उसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हेंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया था।

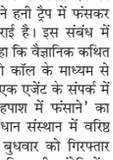

कर्नाटक चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के बीच दिख रहा शानदार मुकाबला

बेगलुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने आखिरी चरण में है। तमाम राजनीतिक दलों ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि, राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। लेकिन जीडीएस को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए और वह किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है। इसको लेकर लगातार ओपिनियन पोल आ रहे हैं। ज्यादातर ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। तो वहीं जी न्यूज़-रूड्डह्लह्द्ब5द्द के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते दिख रही है। फिलहाल कर्नाटक में चुनावी वादों का भरमार है। सभी दल अपने अपने स्तर पर इन लोगों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

एबीपी-सी वोटर के ओपिनियन पोल की मानें तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। भाजपा और जेडीएस को नुकसान हो सकता है। एबीपी-सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा के खाते में 74 से 86 सीटें मिलने की संभावना है जबकि जेडीएस के पास 23 से 35 सीटें जा सकती है। वोट शेयर के मामले में भी भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस के पास वोट शेयर 40त्न तक जा सकती है जबकि भाजपा के पास 35 फ़ीसदी रहने की संभावना है। जेडीएस को 17 फ़ीसदी वोट मिल सकते हैं।

इंडिया टुडे सी वोटर के मुताबिक भी कर्नाटक में भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। 2018 की तुलना में पार्टी को 24 सीटें कम मिलेंगी। पार्टी को 74 से 86 सीटें मिलने की

संभावना जताई गई है। ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी लोगों से राय मांगा गया। ताजा सर्वे के मुताबिक सिद्धारमैया अभी भी मुख्यमंत्री पद की रेस में लोगों की पसंद है। 42त्न लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं भाजपा के बसवराज बोम्मई को 31 फ़ीसदी लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एनडीटीवी और सीएसडीएस के सर्वे में 40 फ़ीसदी लोगों ने सिद्धारमैया को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पसंद किया है। वहीं, बसवराज बोम्मई को सिर्फ 42 फ़ीसदी लोग ही सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। एचडी कुमारास्वामी को 15 फ़ीसदी, डीके शिवकुमार को चार और बीएस येद्दयुरप्पा को पांच फ़ीसदी लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं।

मुख्य चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहां 67 फ़ीसदी लोगों का मानना है कि महंगाई ज्यादा हुई है। गरीबी को लेकर भी लोगों ने चिंता जाहिर की है। 51त्न लोगों ने दावा किया है कि भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं, 35 फ़ीसदी लोगों को इसमें कोई अंतर नजर नहीं आया। जी न्यूज़-रूड्डह्लह्द्ब5द्द के सर्वे की माने तो भाजपा वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। भाजपा को 103 से 115 सीटें मिल सकती है जबकि कांग्रेस के साथ में में 79 से 91 सीटें जा सकती हैं। जेडीएस 26 से 36 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रहेगी जबकि 1 से 3 सीट अन्य के खाते में जाएगी। वोट शेयरों की बात करें तो यहां भाजपा को 42 फ़ीसदी, कांग्रेस को 40 फ़ीसदी और जेडीएस को 15 फ़ीसदी मिलती हुई दिखाई दे रही है।

वर्तमान में कर्नाटक में देखें तो राजनीतिक वार-पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भाजपा के प्रचार की कमान खुद संभाल ली है। वह लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पीएफआई, आरक्षण, बजरंग दल फिलहाल बड़े मुद्दे बन चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे तो जनता किसके पक्ष में जाती है। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।

मल्लिकार्जुन खड़गे हार का दोष लेंगे

कर्नाटक में पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि अगर उनकी पार्टी 10 मई को चुनाव हार जाती है तो वह कोई भी दोष लेने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है क्योंकि वह 2014 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद से अपने फिसलते चुनावी प्रदर्शन को उलटने के लिए तरस रही है।

रावघाट रेललाइन का निर्माण कार्य अगस्त महीने से शुरू किए जाने की पूरी संभावना

रेललाइन का निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड (आरबीएनएल) को सौंपने पर भी सहमति बनी, जुलाई तक पूरी होगी डीपीआर

जगदलपुर। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में हुई एक बैठक में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रायपुर और बस्तर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रावघाट-जगदलपुर रेललाइन का निर्माण कार्य अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा। रेललाइन का निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड (आरबीएनएल) को सौंपने पर भी सहमति बन गई है।

आरबीएनएल ने ही रावघाट से दल्लीराजहरा तक 95 किलोमीटर की रेललाइन का निर्माण किया है। राजनांदगांव के सांसद एवं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी संतोष पांडे, भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना के नेतृत्व में गुरुवार को दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ लगभग एक घंटे चले बैठक में रेल मंत्री ने रेलवे से जुड़ी आधा दर्जन मांगों पर भी चर्चा के बाद सहमति दे दी है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सदस्य के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार रेलमंत्री ने बस्तर को रायपुर से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 2,538 करोड़ रुपये की लागत वाली 140 किलोमीटर की रावघाट-जगदलपुर रेललाइन परियोजना का काम बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छोड़ने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

बस्तर में रेलवे के विस्तार के लिए रावघाट-जगदलपुर रेललाइन का नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जा रहा है। जुलाई तक यह काम पूरा होने की उम्मीद है। बरसात के बाद अगस्त महीने से रेललाइन का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य है।

केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर भाजपा ने जताया आभार

इस साल के नवंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल में रावघाट रेल परियोजना का मामला गरमाया हुआ है। प्रदेश के रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन की स्वीकृति पर बस्तर संभाग प्रभारी सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का आभार जताया है।

बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद संतोष पांडे और पूर्व मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी दिल्ली में मुलाकात की है। ज्ञापन सौंपकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण के लिए सहमति दी है। केंद्रीय रेल मंत्री ने इसका डीपीआर जुलाई 2023 तक करने का आश्वासन दिया है।

अलग-अलग चरणों में हो रहा काम

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग-अलग चरणों में काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का डीपीआर जुलाई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ हिस्सों में काम हो चुका है। शेष जगहों पर भी डीपीओर बनने के बाद काम में तेजी आएगी। साल 1993 से लंबित इस परियोजना के पूरा होने की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है।

बता दें कि रावघाट रेल परियोजना प्रदेश के नक्सल इलाकों को रेल कॉरिडोर से जोड़ने की देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। दल्लीराजहरा-जगदलपुर-रावघाट रेल लाइन निर्माण की मांग दशकों पुरानी है। वर्ष 1993 में योजना आयोग से इस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। साल 2011 में इस ट्रेक पर काम शुरू भी हुआ है। इसके बनने से बस्तर संभाग का सीधा कनेक्शन रायपुर से जुड़ जाएगा। वहीं लोगों को जगदलपुर से रायपुर मात्र 3 से 4 घंटे में पहुंच सकेंगे।

स्काउट्स गाइड्स ने हरियाणा में किया एडवेंचर

कोरबा। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पर्वतारोहण व्यक्तित्व विकास एवं आपदा प्रबंधन शिविर में जिले के स्काउट्स, गाइड्स ने भागीदारी की। यह शिविर कोरबा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के गदपुरी हरियाणा स्थित नेशनल यूथ कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। स्वामी आत्मानंद विद्यालय पंप हाउस कोरबा के स्काउट वैभव डहरिया, लोकेश चौहान, रोहित मानिकपुरी, गाइड मनीषा साहू, पुष्पांजलि साहू, उजाला कुमारी ने कैम्प में भाग लिया। दल का नेतृत्व जिला संगठन आयुक्त स्काउट डीगम्बर सिंह कौशिक ने किया। प्रतिभागी स्काउट्स, गाइड्स ने राइफल शूटिंग, आर्चरी, कंमाडो क्लास लेटर, क्रांसिंग मंकी, ब्रिज क्रॉस आदि एडवेंचर गतिविधियों में भागीदारी की। प्रतिभागियों ने आगरा, नई दिल्ली का भी भ्रमण किया।

श्रम विभाग की टीम ने रेस्क्यू आपरेशन से 12 युवाओं को कराया ठेकेदार से मुक्त

मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी। सिंघाभेड़ी-आमाटोला के रहने वाले युवाओं को मोबाइल कंपनी सैमसंग के एक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया था जिसमें राजनांदगांव जिले के छुरिया के तीन नौजवान भी शामिल थे। बंधक युवाओं ने सीधे कलेक्टर एस. जयवर्धन को फोन पर अपने साथ हो रहे बर्ताव को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर ने एसपी वाई. अक्षय कुमार से मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजनांदगांव के श्रम विभाग की टीम ने एक रेस्क्यू आपरेशन से 12 युवाओं को ठेकेदार से मुक्त कराया।

मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल के महीने में एक व्यक्ति के जरिये कुल 12 युवक चेन्नई के नजदीक कांचीपुरम में संचालित एक सैमसंग फैक्ट्री में काम करने गए थे। इस दौरान ठेकेदार द्वारा सभी के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज किया जाता था। ठेकेदार के रवैये से दुखी होकर युवक जब बिना बताए घर लौटने के लिए बस स्टैंड पहुंचे तो सभी को बलातपूर्वक वापस कारखाने ले जाया गया। इस दौरान युवाओं को डराया धमकाया गया। साथ ही मारकर फेंकने की धमकी दी गई। किसी तरह युवकों ने हिम्मत जुटाते कलेक्टर को सीधे अपने साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जानकारी देते रिहाई के लिए गुहार लगाई।

आखिरकार तीन दिन के रेस्क्यू आपरेशन के बाद कांजीपुरम के प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी को सकुशल बाहर निकाला और ट्रेन में घर जाने के लिए छोड़ दिया। शुक्रवार को बंधक रहे युवक टिकेन्द्र राजपूत, कामेश चंद्रवंशी व महेश कुमार ने अपनी आपबीती सुनाते प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस संबंध में श्रम निरीक्षक तारम सिंह मंडावी ने बताया कि कांजीपुरम के अफसरों के साथ एक रेस्क्यू आपरेशन कर युवाओं को सुरक्षित छुड़ाया गया है। कांजीपुरम प्रशासन मामले की जांच कर रही है।

हसदेव पॉवर प्लांट के यूनिट 4 ने बिना थमे 111 दिन लगातार बिजली उत्पादन का रिकार्ड बनाया

38 साल में पहली बार इतने अधिक दिन बिना थमें चलने का बना कीर्तिमान

कोरबा। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम एचटीपीपी की 210 मेगावाट की इकाई क्रमांक चार ने बिना रूके 111 दिन नौ घंटे 53 मिनट से अधिक समय तक लगातार चलने का रिकार्ड बनाया है। एक तरफ 38 साल पुरानी यह यूनिट लगातार बिजली उत्पादन का रिकार्ड बना रही, वहीं नए मड़वा संयंत्र की इकाई रखरखाव में करोड़ों खर्च के बाद भी एक माह में ही हाफ जाती है।

विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम स्थित एचटीपीपी संयंत्र की इस चार नंबर इकाई में एबीएल बायलर एसीसी बेबकाक लिमिटेड, जर्मनी की मशीनें लगी हैं। इस कंपनी के देशभर में स्थापित पुराने संयंत्र इतनी अधिक अवधि तक नहीं चल पाती हैं। इस तकनीक वाले कई प्लांट बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में निरंतर संचालन करना एक बड़ी उपलब्धि है। विद्युत कंपनी के अध्यक्ष अंकित आनंद एवं जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी संजीव कटियार ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते आगे भी नया रिकार्ड बनाने कहा।

एमडी कटियार ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा टीम भावना के साथ ईमानदारी, निष्ठा और कड़ी मेहनत से किए गए कार्य से यह उपलब्धि हासिल हुई है। कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आगे भी उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। यहां बताना होगा कि हसदेव ताप विद्युत गृह में 210-210 मेगावाट की चार यूनिट हैं, जिनकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसमें से यूनिट क्रमांक चार ने गुरूवार की सुबह 8.34 बजे अपने ही पूर्व स्थापित निरंतर संचालन अवधि के कीर्तिमान 111 दिन नौ घंटे, 53 मिनट को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया।

वर्तमान में यह संयंत्र निरंतर संचालन में है। यह उपलब्धि लगातार मानिटरिंग, उच्च रखरखाव और खास सतर्कता के कारण हासिल हो सकी है। सामान्यत: इतना समय तक चलने पर संयंत्र में मेंटेनेस की जरूरत पड़ जाती थी, इस बार ऐसी स्थिति नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि 210 मेगावाट के एबीएल बायलर को जनरेशन कंपनी में कार्यरत अभियंता व कर्मचारी बहुत अच्छे ढंग से चला रहें हैं। इसके अलावा हसदेव ताप विद्युत गृह के यूनिट क्रमांक-दो से भी 112 दिन, 15 घंटे एवं 6 मिनट तक लगातार विद्युत उत्पादन जारी है एवं यह भी नये कीर्तिमान दर्ज करने की ओर अग्रसर है।

वर्ष 2016 को अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा संयंत्र की 500-500 मेगावाट की दोनों इकाइयां स्थापित की गई। इसके बाद से किसी न किसी एक इकाई में तकनीकी खराबी आ रही है। सभी प्रमुख संयंत्र संचालन में सबसे अधिक सालाना खर्च मड़वा संयंत्र में हो रहा है। अन्य संयंत्रों में जहां एएफसी कास्ट सालाना चार से छह करोड़ के बीच है, जबकि मड़वा संयंत्र में एएफसी करीब 1500 करोड़ के करीब है। विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों में तीन हजार करोड़ से अधिक का खर्च इस मद पर हो रहा। इसके बावजूद मड़वा की इकाइयां नियमित तौर पर नहीं चल रही। गुरूवार को वर्षा नहीं होने से तेज गर्मी का असर दिखाई दिया। इससे एक बार फिर राज्य में बिजली की मांग बढ़ने लगी।

एचएमएस के सदस्यों ने जेबीसीसीआई सदस्य से मुलाकात कर श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

कोरबा। कोयला कर्मियों के 11 वें वेतनमान सहित नान एमजीबी मुद्दों को लेकर संगठनों ने चार्टर आफ डिमांड सौंपा है। जेबीसीसीआई की नवमी बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगली बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। श्रमिकों की विभिन्न मांगे लंबित है। जिसे लेकर स्थानीय एचएमएस नेताओं ने संगठन के पदाधिकारी व जेबीसीसीआई सदस्य से मुलाकात कर चर्चा की है।

कोयला मजदूर सभा एचएमएस एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के सेक्रेटरी एस सी मंसूरी, कार्यवाहक अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार, संगठन मंत्री अनंत सिंह, एस डी मानिकपुरी ने जेबीसीसीआई मेंबर व केंद्रीय अध्यक्ष डब्ल्यूसीएल शिव कुमार यादव से उनके निवास स्थान पर सौजन्य मुलाकात की। जिसमें जेबीसीसीआई 11 के होने वाले बेच बोर्ड के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। श्री यादव द्वारा जेबीसीसीआई 11 की नवमी बैठक में हुए निर्णय और चर्चा की विस्तृत जानकारी दी गई। गेवरा क्षेत्र के पदाधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया हैं कि उच्च कैपेसिटी के डंपर, सावेल, डोजर, ग्रेटर ड्रिल चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए कैडर स्कीम व उच्च वेतनमान दिलाए जाए। सुपरवाइजर ग्रेड के लिए ओटी सीलिंग जो निर्धारित है उसे बंद कराया जाए। जिस पद का कार्य कोल इंडिया में हो रहा है और उसका केडर स्कीम नहीं है। ब्लास्टिंग ट्रूमैन, केबल मैन आदि का कैडर स्कीम बनाया जाए। साथ ही कर्मचारियों के रिटायरमेंट पश्चात मेडिकल सुविधा के लिए जो 40000 रूपए की कटौती की गई है उस पर अधिकारियों की तरह सुविधा प्रदान करने की मांग की गई। श्रमिकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। यादव द्वारा आश्वासन दिया गया हैं कि वेज बोर्ड व मिलने वाली सुविधाओं में कर्मचारियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

टिप्पर-ट्रेक्टर आगजनी में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पेद्दाकोड़ेपाल कैम्प से थाना नैमेड़ एवं केरिपु 222 की संयुक्त टीम सर्चिंग पर पेद्दाकोड़ेपाल की ओर निकली थी। इस दौरान 2 नक्सली सुखराम पूनेम (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) पिता स्व. बुधरू पूनेम उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी स्कूलपारा छोटे तुंगाली थाना जांगला एवं मोटू मुचाकी (पोटेनार सीएनएम सदस्य) पिता सोनू मुचाकी उम्र 19 वर्ष जाति मुरिया निवासी स्कूलपारा छोटे तुंगाली थाना जांगला को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार दोनों नक्सली 14 मार्च 2023 को मिनगाचल नदी पार से रेत परिवहन कर रहे 2 टिप्पर एवं 1 ट्रेक्टर की आगजनी की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। जिनके विरूद्ध थाना नैमेड़ में कार्यवाही उपरान्त न्यायिक रिमाण्ड पर आज न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया है।

खेत में काम के दौरान पलटा ट्रैक्टर, दो ने गवाई जान

जगदलपुर। जगदलपुर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां गुरुवार की शाम एक ट्रैक्टर के पलट जाने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई और तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर आ पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भानपुरी भेजा गया। भानपुरी थाना प्रभारी किशोर केवट ने बताया कि गुरुवार शाम पांच बजे ग्राम कावड़गांव के सुखरु कोर्राम अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम करा रहा था। जुताई वाले ट्रैक्टर में एक ही परिवार के सदस्य सवार होकर खेत में काम कर रहे थे। जब खेत का काम खत्म हुआ और सभी ट्रैक्टर में वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी इसी दौरान खेत के भीतर ही वाहन चलते चलते अनियंत्रित हो गया और पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे कुलु (6) और कंवल (7) दब गये, जिससे दोनों की मौत हो गई।

मीडिया एसोसिएशन ने पशु पक्षियों के जल की व्यवस्था के लिए किया कोटना भेंट

कोरबा। गुरूवार को डिजिटल मीडिया एसोसिएशन कोरबा के द्वारा नगर पालिक निगम को पशु पक्षियों के जल की व्यवस्था हेतु कोटना भेंट किया गया। जिसके लिए निगम ने एसोसिएशन का धन्यवाद ज्ञापित किया। डिजिटल मिडिया एसोसिएशन ने बढ़ते गर्मी को देखते हुवे पशु-पक्षियों हेतु जल की व्यवस्था करने एक नई पहल की है जिसमे, एसोसिएशन द्वारा निगम को कोटना प्रदान किया गया। जिसे शहर के विभिन्न स्थानों में स्थापित कर पशुओं हेतु जल की व्यवस्था की जाएगी। एसोसिएशन की इस पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। अपर आयुक्त ने लोगो से की अपील अपर आयुक्त ने लोगों से अपील करते हुवे कहा कि शहर के विभिन्न स्थानों में कोटना को रखा जाएगा तथा जिलेवासियों को भी आमंत्रित करते हुए कहा की जिस किसी को भी कोटना चहिए वे प्राप्त कर सकते हैख साथ ही डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के इस पहल का स्वागत किया।

जिला दण्डाधिकारी ने फरीद खान को किया जिला बदर

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव झा ने जिले के आदतन अपराधी फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान पिता कमरूद्दीन उम्र 32 वर्ष, निवासी साकिन नया बस स्टैण्ड कटघोरा को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। झा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202111050400020/2021-22 में पारित आदेश 04/05/2023 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- कोरबा तथा समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। उन्होंने फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान पिता कमरूद्दीन, निवासी साकिन नया बस स्टैण्ड कटघोरा को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

महुआ शराब का अवैध निर्माण पुलिस ने चार भट्ठियों को तोड़ा

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महुआ शराब का अवैध निर्माण कर रहे चार भट्टियों को तोड़ दिया है। वहीं मौके पर 30 बोरा महुआ पास को भी नष्ट किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चक्रधर नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रेगड़ा के जंगल नदी किनारे कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से शराब भट्ठियों पर महुआ शराब तैयार करते हैं। सूचना पर थाना प्रभारी ने तत्काल आरक्षक अभय यादव, चुडामणी गुप्ता और चंद्र कुमार बंजारे के साथ ग्राम रेगड़ा पहुंचे । जहां पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान की घेराबंदी कर दबिश दिया गया। यहां मौके कोई नहीं मिला बल्कि यहां नदी किनारे बनाये गये 4 अवैध महुआ शराब भट्ठियों को तोड़कर मौके पर रखे हुये करीब 30 बोरा महुआ पास का नष्टीकरण कर शराब बनाने के पात्र को जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया।

आंशिक अधिग्रहण रद्द कर संपूर्ण जमीन का किया जाएगा अर्जन: प्रबंधन

कोरबा। खदान प्रभावित गांव रलिया, भिलाईबाजार का आंशिक भू-अर्जन रदद् कर संपूर्ण जमीन का अर्जन किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की गई है, और जल्द ही धारा चार की प्रकाशन किया जाएगा। प्रबंधन ने भू-विस्थापितों के साथ बैठक कर आश्वस्त किया कि सभी पात्र भू-विस्थापित को रोजगार मिलेगा। जहां पर संशोधन की आवश्यकता है, वहां उपाय किया जाएगा। खाता संयोजन का मामला बोर्ड में शामिल की जाएगी।

बैठक में प्रबंधन ने कहा कि संगठन के मांगो पर एसईसीएल गंभीरता से विचार कर रही है। त्रिपक्षीय समझौते के बाद कई महत्वपूर्ण पालिसी शामिल किए गए हैं। पुराने रोजगार के प्रकरणों सहित नए रोजगार प्रदान किए गए। साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार के पट्टों में सभी सुविधाएं लागू होगी और वन भूमि शासकीय भूमि पर निर्भर आदिवासी व परंपरागत रूप से रह रहे लोगों भूमिहीन किसानों को लाभ दी जाएगी । मेगा प्रोजेक्ट में भू. विस्थापित परिवारों के लिए लागू बसाहट, ठेका सहित अन्य सभी सुविधाएं कोरबा क्षेत्र और एसईसीएल के दूसरे क्षेत्रों में लागू करने के लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। जिसे बोर्ड में पारित होने के लिए रखा गया हैं। इसी तरह नए दर पर जमीन का मुआवजा के लिए भी कार्रवाई जारी है। बैठक में पूर्व में अर्जित और खदान बंद होने पर मूल खातेदारों को जमीन वापसी होगी। सीबीए में संशोधन की प्रकिया पूरी हो चुकी है और लोकसभा व राज्य सभा में स्वीकृत हेतु भेजी गई है। भू-विस्थापित बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जाधानी संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि 11 सूत्रीय मांगों पर पांच चरणों में आंदोलन की घोषणा की गई थी और गेवरा तथा दीपका बंद के बाद वार्ता शुरू की गई है। कुसमुंडा में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में सभी मांगो पर सकारात्मक निर्णय लिया गया और एक माह में इस प्रगति होने की आश्वासन दिया गया है। यदि प्रबंधन वादाखिलाफी करती है, तो कुसमुंडा से ही आंदोलन शुरू होगा।

एसईसीएल के कुसमुंडा के सभाकक्ष में त्रिपक्षीय वार्ता में बिलासपुर मुख्यालय से श्रम शक्ति व विभिन्न विभाग प्रमुखों समेत जिले के महाप्रबंधक और तहसीलदार दीपका और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी व भू-विस्थापित मौजूद रहे। वार्ता में निदेशक मंडल के सदस्यों को भी शामिल होना था, किंतु दिल्ली में कोल इंडिया के बोर्ड कमेटी की मीटिंग में जाने के कारण उपस्थित नही हो सके। इसलिए भू-विस्थापित हाथ में तख्ती लेकर विरोध दर्ज कराते हुए वार्ता में शामिल हुए। पांच घंटा चली बैठक में के दौरान ज्ञापन के सभी एजेंडा समेत अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कारखाना लगाने लोन दिलाने के नाम पर नागपुर के व्यक्ति ने पूर्व सरपंच से की धोखाधड़ी

खैरागढ़। पांडादाह के रहने वाले एक पूर्व सरपंच से कारखाना लगाने के लिए 40-50 लाख रुपए बिना ब्याज लोन दिलाने का झांसा देकर नागपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए जांच में लिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पांडादाह के पूर्व सरपंच मोहम्मद गौस डेढ़ साल पहले दिसंबर 2021 को नागपुर में रहने वाले अपने भतीजे अब्दुल सलाम के संग एक दरगाह से दर्शन कर गुलशन नगर चौक में स्थित चाय की दुकान में रूके। चाय पीने के बीच पूर्व सरपंच ने अपने भतीजे से पांडादाह में उद्योग स्थापि करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत पर चर्चा की। वहां मौजूद अनिल ठाकुर नामक व्यक्ति ने खुद को इन्कम टैक्स अधिवक्ता बताते हुए बिना के लोन दिलाने का भरोसा दिया। उसकी बात सुनकर चाचा-भतीजा लोन लेने की इच्छा जाहिर करते उससे बातचीत शुरू की। अनिल ठाकुर ने बिना ब्याज लोन दिलाने के एवज में 10 लाख रुपए सेवा शुल्क मांगा। दोनों सेवा शुल्क देने तैयार हो गए। पूर्व सरपंच के गृहग्राम पांडादाह पहुंचकर लोन संबंधी दस्तावेज लेकर आरोपी ने 70 हजार रुपए नगद लिए। इस तरह वह अलग-अलग तारीखों में 4 लाख रुपए लिया। बाद में पूर्व सरपंच को लोन सेंशन होने की जानकारी देकर शेष रकम तुरंत जमा करने को कहा। भोपाल में रहने वाले अपने साथी से 3 लाख रुपए उधार लिए। आरोपी द्वारा बनाने पर अपने पुत्र के खाते से रकम को जमा किया, लेकिन लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार पूर्व सरपंच को अपनी ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

एनसीपी की कमिटी ने पवार का इस्तीफा नामंजूर किया

मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी उथल-पुथल ने अब एक नया करवट लिया है, दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के बाद से पवार के समर्थक काफी निराश थे, आज नए एनसीपी चीफ के लिए गठित कमिटी ने पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और उनसे अध्यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह किया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार ने दो मई को अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने आगे की कार्रवाई और नया अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी नेताओं की एक कमेटी गठित की, आज हमने इस कमेटी की मीटिंग की। कई नेताओं ने पवार साहेब से मुलाकात की जिसमें मैं भी शामिल था। हमने उनसे बार-बार ये आग्रह किया कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें क्योंकि देश और पार्टी को इस घड़ी में उनकी ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांगों को मद्देनज़र शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया।

मुखपत्र सामना ने साधा एनसीपी पर निशाना

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संबंधों में खिंचाव सामने आ रहा है। शिवसेना यूबीटी की ओर से एनसीपी की आलोचना की बात है तो आपको बता दें कि पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के शरद पवार के फैसले पर आंसू बहाने वाले उनकी पार्टी के कई नेताओं का एक पैर भारतीय जनता पार्टी और दूसरा पैर एनसीपी में है। 'सामना' में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया कि एनसीपी के कई नेता आज (भाजपा की) दहलीज पर हैं और पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी की पोल खोल दी है। सामना में कहा गया है कि अगर पवार के दिमाग में अपनी पार्टी को विभाजित होते देखने के बजाय, गरिमा के साथ पार्टी छोड़ने का विचार आया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संपादकीय में कहा गया, ''पवार द्वारा सेवानिवृत्ति की घोषणा करते ही कई प्रमुख नेताओं के आंसू छलक पड़े।

ईडी, सीबीआई वोट हासिल करने में भाजपा की मदद नहीं करेंगी

शमशेरगंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियां अगले साल के लोकसभा चुनावों में वोट हासिल करने में उसकी मदद नहीं करेंगी। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मिलकर मुकाबला करने का आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद राज्य प्रशासन को गंगा का कटाव रोकने के लिए कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि गंगा का कटाव मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में एक बड़ा मुद्दा है। इस अवसर पर ममता ने उन लोगों को 'पट्टे' (जमीन के दस्तावेज) सौंपे।

बंगला विवाद पर भाजपा ने केजरीवाल को घेरा

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के सौंदर्यीकरण को लेकर राजनीतिक तेज है। आज एक बार फिर से भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर जवाब देना चाहिए। अपने बयान में त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल के आलीशान महल से उनके बारे में कई सच्चाईयां खुलती हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के महल में जिस तरह का वैभव दिखाता है, वह सद्दाम हुसैन और किम जोंग के महलों जैसा लगता है! उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि इस तरह केजरीवाल की पार्टी ने न केवल राष्ट्रीय कद, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कद भी हासिल किया है! अपना हमला जारी रखते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि उनके आलीशान महल में सेंसर वाले दरवाजे हैं। उन्होंने कहा कि रिमोट से सब कुछ नियंत्रित करते हैं केजरीवाल, यहां तक कि उनकी पार्टी भी।

30 साल में मार दिए लाखों शिया

पाकिस्तान। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि पिछले 25-30 वर्षों में, न केवल पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सऊदी अरब और इराक में लाखों शिया मारे जा रहे हैं। कोई अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है और न ही संयुक्त राष्ट्रों द्वारा कोई हस्तक्षेप है। दुख की बात तो यह है कि खुद को इस्लामिक देशों का नेता कहने वाला सऊदी अरब खुलेआम इन आतंकवादियों का समर्थन करता है। पाकिस्तान की जियो न्यूज के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी कुर्रम तहसील में कम से कम सात शिक्षक मारे गए। स्थानीय पुलिस ने कहा कि अज्ञात बंदूकधारियों ने सरकारी हाई स्कूल तारी मंगल के स्टाफ रूम में शिक्षकों को गोली मार दी। पाराचिनार में एक अन्य घटना में, चलती गाड़ी में एक शिक्षक की मौत हो गई - एक दिन में मारे गए शिक्षकों की कुल संख्या आठ हो गई। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी कबायली जिले में निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में आठ स्कूली शिक्षकों की मौत हो गई।

'द केरला स्टोरी' फिल्म की चर्चा कर प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस पर साधा निशाना

पैसों के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ रही कांग्रेस : मोदी

बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्लारी के म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर अपने इको सिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वे जनता को भ्रमित कर दें। प्रधानमंत्री ने

कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदें है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टिकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। मोदी ने द केरल स्टोरी फिल्म का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आकंती प्रवृत्तिवालों से ये राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे।

मोदी ने कहा कि फिल्म केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। मेहनती, प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के लिए जाने जाने वाले राज्य केरल में कैसे आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस ने आतंकवाद को पाला-पोषा और उसे पनाह दी। उन्होंने कहा कि मैं ये देख कर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, ड्रग्स इंडस्ट्री, खेती, किसानी और गौरवमयी संस्कृति सब कुछ तबाह हो जाएगी।

सपा-बसपा पर बरसे योगी

कहा- आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट हैं

उत्तर प्रदेश । निकाय चुनाव को लेकर राज्य में प्रचार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार के दौरान उन्होंने एक बार फिर से राज्य के पिछली सरकारों के बहाने सपा और बसपा पर निशाना साधा है। मेरठ में जनसभा के दौरान योगी ने कहा कि 2017 से पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको आधारभूत संरचना और गरीब से मतलब नहीं था। योगी ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे।

मुख्यमंत्री ने सपा-बसपा पर हमला करते हुए कहा कि वे कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजना में डकैती डालकर अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये अवसरवादी और परिवारवादी ही नहीं थे, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ाते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट हैं। योगी ने कहा कि 6 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश की जनता सुरक्षित है और विकास के बारे में सोच रही है। केवल वंशवादी राजनीति और माफिया संकट में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की छवि काफी बदली है। अब लोग यूपी के लोगों का सम्मान करते हैं। पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छिपाते थे, अब गर्व से कहते हैं कि हम यूपी के हैं।

इसके साथ ही योगी ने कहा कि मेरठ को पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि सपा और लोक दल का गठबंधन केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, यह अराजकतावादी गठबंधन भी है।

योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने समाज में जाति और मत-मजहब के नाम पर खाई पैदा की है। उन्होंने कहा कि अब सरकार दीपावली और होली में मुफ्त गैस सिलेंडर देगी, अब बस्ती में जब बेटी का जन्म होता है तो मंगल गीत गाये जाते हैं कि घर में सुमंगला आई है। सरकार अब बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई-लिखाई और विवाह तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले नगरों में शोहदों का आतंक हुआ करता था। व्यापारी से रंगदारी वसूली जाती थी। मगर आज हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं बल्कि टैबलेट देने का काम किया है।

देवेगौड़ा ने एक ही बयान में साधा मोदी-राहुल पर निशाना

बेंगलुरु। जनता दल सेक्यूलर के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हासन रैली में जेडीएस के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीएस अध्यक्ष देवेगौड़ा ने अपने बयान में न केवल पीएम मोदी बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया है। देवेगौड़ा ने अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिलेड पार्टी कहने पर पीएम मोदी की तीखी आलोचना की और कहा, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी शोभनीय नहीं है और कम से कम उन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी के स्तर पर उतरकर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे उनसे मान-सम्मान में कमी आती है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वही बातें दोहराईं, जो राहुल गांधी ने पिछली बार कही थी। यह ठीक नहीं है।

बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास : शेट्टार

बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। वहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा हमलावार है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि प्रदेश में जाति एवं धर्म के आधार पर 'नफरत फैलाने' के लिए बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर राजनीति जारी है। भाजपा और हिन्दूवादी संगठन कांग्रेस पर हमलावर है। इस सब के बीच हाल में ही भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर, कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र में कई बिंदु हैं, हम इस मुद्दे को क्यों सीमित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाना केंद्र सरकार की शक्ति है। राज्य सरकार का नहीं।

चुनाव के बाद भाजपा का एक इंजन कबाड़ में चला जाएगा : मोइली

मंगलुरु। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के 'डबल इंजन' में से एक को कबाड़ में भेज दिया जाएगा। मोइली ने संवाददाताओं से कहा, 'विधानसभा चुनाव के बाद एक इंजन कबाड़ में भेज दिया जाएगा और दूसरा भी 2024 में कबाड़ में चला जाएगा।' उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने यहां डबल इंजन लगाये थे क्योंकि एक इंजन से काम नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने कहा कि दोनों तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को नियंत्रित कर रही है जिसमें सुरक्षा संबंधी एजेंसियां भी शामिल हैं और भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो गयी है।

खेल
प्रमुख समाचार

मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबला आज

चेन्नई। पिछले तीन मैचा में महज एक अंक बना सकी चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में शनिवार को मुंबई इंडियंस को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेगी हालांकि मुंबई के हौसले बुलंद है और यह उसका पसंदीदा मैदान भी है। पांच बार की चैम्पियन मुंबई ने एम ए चिदंबरम स्टेडियम पर पिछले दो मुकाबले जीते हैं। उसने 2019 में यहां चेन्नई को हराया और करीब चार साल बाद यहां चिर प्रतिद्वंद्वी चार बार की चैम्पियन टीम से खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम का लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ पिछला मैच बारिश की भेंट हो गया जबकि उससे पहले दो मैचों में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स के खिलाफ 30 अप्रैल को आखिरी गेंद पर पराजय का सामना करने वाली चेन्नई को उम्मीद है कि इस बार वह अपने दर्शकों को निराश नहीं करेगी ।

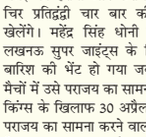

डेवोन कॉवे (414 रन) और रूतुराज गायकवाड़ (354 रन) ने टीम को अच्छी शुरूआत दी है लेकिन मध्यक्रम उसका फायदा नहीं उठा सका । अनुभवी अजिंक्य रहाणे और युवा शिवम दुबे ने रन बनाये हैं लेकिन अंबाती रायुडू और मोईन अली का बल्ला कमोबेश खामोश ही रहा है । बल्लेबाजी क्रम में काफी नीचे उतर रहे धोनी ने कुछ अच्छे शॉट खेले हैं लेकिन उनके प्रशंसक इस बात पर हैरान हैं कि वह खराब फॉर्म से जूझ रहे रायुडू और रविंद्र जडेजा को अपने से पहले बल्लेबाजी के लिये क्यो भेज रहे हैं । चेन्नई ने रहाणे की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पहले मैच में मुंबई को हराया था और रहाणे एक बार फिर उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। दीपक चाहर की वापसी से गेंदबाजी मजबूत हुई है लेकिन तुषार देशपांडे (17 विकेट , इकॉनामी रेट 12.11) ने काफी रन दिये हैं। जडेजा ने गेंदबाजी अच्छी की है लेकिन बल्ले से कोई कमाल नहीं कर सके।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 695 अंक टूटा निफ्टी 18,100 के नीचे

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले रुझानों के बीच भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन धड़ाम हो गए। घरेलू स्तर पर एचडीएफसी एवं एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली होने से शुक्रवार को दोनों मानक सूचकांकों में एक फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स 695 अंक टूटकर 61,054.29 पर बंद हुआ । वहीं, निफ्टी में भी 187 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले सेंसेक्स 555.95 अंक यानी 0.91 फीसदी चढ़कर 61,749.25 अंक पर बंद हुआ था। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 694.96 अंक यानी 1.13 फीसदी टूटकर 61,054.29 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 61,585.50 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 61,002.17 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 186.80 अंक यानी 1.02 फीसदी लुढ़का।

अप्रैल में कम हुई डीमैट अकाउंट खुलने की रफ्तार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट खुलने की दर फिर से धीमी पड़ती जा रही है। मासिक आधार पर डीमैट अकाउंट खुलने की दर अप्रैल में 16 लाख पर पहुंच गई, जो कि दिसंबर 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इसके पहले मार्च में भी अकाउंट खुलने का आंकड़ा मार्च 2020 के स्तर पर आ गया था। मार्च माह में करीब 19 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। इसके साथ ही यूक्रेन-रूस युद्ध, महंगाई दर में इजाफा और विकसित देशों में बैंकिंग संकट की वजह से निवेशकों के रुख में कमजोरी देखने को मिली। डीमैट अकाउंट खुलने का आंकड़ा वित्त वर्ष- 22 के मुकाबले 23 में भी कमजोर देखा गया है। जहां, वित्त वर्ष-22 में 29 लाख नए डीमैट अकाउंट औसतन हर महीने खुले; वहीं, वित्त वर्ष-23 में 20 लाख नए डीमैट अकाउंट का मासिक औसत था।

भारत अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार : टिम कुक

नईदिल्ली। ऐपल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार है और कंपनी इस पर खास ध्यान दे रही है। आईफोन बनाने वाली कंपनी के मुखिया ने यह भी बताया कि भारत में उसके कारोबार ने एक नया तिमाही रिकॉर्ड बनाया है और सालाना आधार पर बेहद मजबूत दो अंकों की वृद्धि हुई है। ऐपल ने पिछले महीने भारत में एक महत्वाकांक्षी खुदरा विस्तार योजना शुरू की और कुक ने दिल्ली और मुंबई में कंपनी के खुदरा स्टोर का उद्घाटन किया। कुक ने तिमाही परिणामों की घोषणा के दौरान कहा, दोनों स्टोर एक शानदार शुरुआत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, भारत में कारोबार को देखते हुए, हमने एक तिमाही रिकॉर्ड बनाया और दो अंकों की बेहद मजबूत सालाना वृद्धि दर्ज की। यह हमारे लिए काफी अच्छी तिमाही थी और भारत आश्वर्यजनक रूप से रोमांचक बाजार है। उन्होंने भारतीय बाजार में गतिशीलता की तारीफ की और कहा कि इसकी जीवंतता अविश्वसनीय है।

जेके बैंक ने 1,197 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया

नईदिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,197 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। बैंक ने बताया कि उसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.39 प्रतिशत है, जो एक दशक में सबसे अधिक है। इसके साथ ही एनपीए आठ साल के निचले स्तर 6.04 प्रतिशत पर है। बैंक ने मार्च 2023 तिमाही में 476 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो अब तक किसी भी तिमाही के मुकाबले सबसे अधिक है। बैंक के प्रवक्ता ने कहा, जम्मू एवं कश्मीर बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,197 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो अब तक सर्वाधिक है। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा, वादे से बेहतर सालाना परिणाम देने का अनुभव शानदार है।

गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए युक्तिकरण और सुधार

हरदीप एस पुरी

मोदी सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए कई उपाय कर रही है। जनवरी, 2021 से फरवरी, 2023 के बीच अंतरराष्ट्रीय गैस की कीमतों में 228% की आश्चर्यजनक वृद्धि के बावजूद, भारत में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि को 83% तक सीमित रखा गया है, जो वैश्विक वृद्धि का केवल एक तिहाई है। राजनीतिक तौर पर विरोध कहने वाले, बढ़ती कीमतों की आलोचना करने की हड़बड़ी में, यह देखने में विफल रहते हैं कि अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने अपने नागरिकों को अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए कितने अच्छे कदम उठाये हैं।

घरेलू प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम), गैस आवंटन को बढ़ाने और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति करने जैसे सक्रिय उपायों के माध्यम से दूरदर्शी शासन-व्यवस्था ने इसे संभव बनाया है। हाल ही में, महत्वपूर्ण एपीएम गैस मूल्य निर्धारण सुधारों की एक श्रृंखला को मंजूरी देने से संबंधित कैबिनेट निर्णय इस उद्देश्य को और आगे बढ़ाएगा। इन सुधारों के द्वारा दो प्रमुख लक्ष्यों को हासिल किया गया है-पहला, अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से भारतीयों की रक्षा करना और गैस आधारित क्षेत्रों में योजनाबद्ध पूंजीगत व्यय से जुड़े निवेश के लिए स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करना और दूसरा, अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) में नवाचार और निवेश को और बढ़ावा देना।

नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 की सीमाओं के कारण युक्तिकरण और सुधार (आर एंड आर) की आवश्यकता सामने आयी, जो हाल तक, चार अंतरराष्ट्रीय

केंद्रों पर गैस की मात्रा-भारित औसत कीमत के आधार पर एपीएम की कीमतों को निर्धारित करती थी। इन कीमतों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण समय अंतराल (6-9 महीने) के बाद पड़ता था और इससे कीमतों में उच्च अस्थिरता मौजूद रहती थी, यहां तक कि पिछले कुछ वर्षों में दो उत्पादक देशों की गैस हब कीमतों ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच एपीएम मूल्य 1.79 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रहा, जो नामित क्षेत्रों के लिए 3.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की उत्पादन लागत से बहुत कम है। इस अवधि के दौरान, पश्चिम भारत में एलएनजी की कीमतों का औसत लगभग 11 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रहा था। संक्षेप में, घरेलू उत्पादन को एलएनजी की कीमतों के 20% से भी कम मूल्य प्राप्त हुआ। हालांकि, रूस-यूक्रेन संकट के बाद अंतरराष्ट्रीय हब की कीमतों में 400% की वृद्धि के कारण सितंबर 2021 में उक्त एपीएम की कीमतें सितंबर 2021 के 1.79 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू हो गईं, जिसका उर्वरक, बिजली और सिटी गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तेल कंपनियों को इस तरह की अस्थिरता से बचाने का फैसला किया, एपीएम की कीमतों को मासिक आधार पर निर्धारित किए जाने वाले भारतीय क्रूड बास्केट मूल्य के 10% पर रखने के साथ-साथ नामांकन क्षेत्रों के लिए 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के अधिकतम सीमा और 4.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की न्यूनतम सीमा तय की गयी। अधिकतम सीमा पिछले 20 वर्षों के भारतीय कच्चे तेल की कीमत (लगभग 65 डॉलर प्रति बीबीएल) के 10% पर निर्धारित की गई है, जबकि न्यूनतम मूल्य का निर्धारण, नामांकन क्षेत्रों से गैस उत्पादन के लिए लगभग 3.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के उत्पादन की सीमांत लागत पर विचार करता है। अधिकांश भारतीय दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध, ब्रेंट से लगभग 13% अधिक पर केन्द्रित रहे थे। एलएनजी अनुबंधों में द्रवीकरण, परिवहन और पुनर्गैसीकरण की लागतों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू गैस, एपीएम कीमतों से 10% अधिक रही।

क्रमशः ...

क्या एनसीपी में टूट से बचाने पवार ने खेला है इस्तीफे का दांव ?

संतोष पाठक

एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के पद से इस्तीफा देने की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के अलावा राष्ट्रीय राजनीति में भी हंगामा खड़ा हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुवों पर खड़ी कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाकर सरकार बनाने का करिश्मा दिखाने वाले पवार की भूमिका को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। यह माना जा रहा था कि अपने राजनीतिक कद और कौशल के कारण लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के विरोध में बनने वाले संभावित मोर्चे में शरद पवार ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा था कि ममता बनर्जी, के. चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा से परेशान कांग्रेस आलाकमान खासतौर से सोनिया गांधी भी शरद पवार पर काफी भरोसा कर रही थीं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे क्रिटिकल समय में शरद पवार को इस्तीफा देने और सक्रिय राजनीति से अलग हो जाने की घोषणा करने की जरूरत क्या थी ? हाल के दिनों में जिस तरह से उनके भतीजे अजित पवार के बार-बार भाजपा के साथ जाने की खबरें आ रही थीं, उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि हो सकता है अपनी पार्टी एनसीपी को टूटने से बचाने के लिए पवार ने अपने इस्तीफे का यह दांव खेला हो क्योंकि इसके बाद पवार और भी ज्यादा ताकतवर बन कर उभरते नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी ही उनसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील कर रही है। शरद पवार अगर अपना इस्तीफा वापस लेकर अध्यक्ष बने रहते हैं तो अजित पवार के लिए अब पार्टी तोड़ना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस माहौल में पार्टी के विधायक शरद पवार से बगावत करने का जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे और यदि पवार इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो भी नया अध्यक्ष उनकी पसंद का ही बनना तय है। दरअसल, शरद पवार ने भविष्य को भांपते हुए हमेशा ही राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति में पार्टी में अलग-अलग चेहरे को तैयार किया। दिल्ली की राजनीति उनकी बेटी सुप्रिया सुले कर रही हैं जिसमें उनके पुराने सहयोगी प्रफुल्ल पटेल सहयोगी की भूमिका में हैं तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार सर्वेसर्वा की स्थिति में रहे हैं। लेकिन यह संतुलन फिलहाल गड़बड़ाता नजर आ रहा है। अजित पवार चाहे जो भी कहें लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनायी थी, उसके बाद एनसीपी के नेताओं को ही उन पर भरोसा नहीं रह गया है। शरद पवार यह बखूबी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी या उनकी बेटी की भूमिका तभी महत्वपूर्ण रह सकती है जब पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत रहे क्योंकि उद्धव ठाकरे की हालत वह देख ही रहे हैं। अगर अजित पवार पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो प्रदेश में एनसीपी कमजोर हो जाएगी और विपक्षी दलों के मोर्चे में उनका इकबाल भी कम हो जाएगा। शायद यही वजह है कि अपने राजनीतिक स्टाइल के मुताबिक शरद पवार ने सभी को चौंकाने वाला यह बड़ा दांव खेल दिया है। अब सबको शरद पवार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार है कि वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या किसी और को पार्टी की कमान सौंपते हैं या फिर स्वयं अध्यक्ष बने रहकर किसी और को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं और बनाते हैं तो किसको बनाते हैं ? पार्टी के नए सैटअप में अजित पवार की आधिकारिक भूमिका क्या रहती है, यह भी देखने वाली बात होगी। यह भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस्तीफे का दांव खेलकर शरद पवार ने कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों को यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं।

हिंदुत्व के मुकाबले विपक्ष का सामाजिक न्याय

विनोद अग्निहोत्री

कर्नाटक चुनावों में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कांग्रेस की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बजरंग दल के बहाने बजरंग बली को आगे करते हुए भाजपा अपने चुनाव प्रचार को ध्रुवीकरण की धार से लैस करके अपनी राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार बेरोजगारी और कुशासन के आरोपों को लेकर बने सत्ता विरोधी रुझान से निपटने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चुनावी सभा में जय बजरंग बली का नारा गूंज रहा है। मोदी और भाजपा के इन तेवरों से साफ जाहिर है कोई भी चुनाव हो भाजपा आखिर तक आते आते हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के हथियार से ही अपने विरोधी की चुनौती का मुकाबला करती है। अगर कर्नाटक में उसका ये हथियार चला तो निश्चित रूप से इस साल होने वाले सभी चुनावों और अगले साल लोकसभा चुनावों में भी भाजपा का सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व का ध्रुवीकरण ही होगा।

विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के पास भाजपा के इस चुनावी हथियार की काट के लिए क्या दांव है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष भी भाजपा के इस दांव से बेखबर नहीं है और इसीलिए उसने भी हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय के जरिए जातीय ध्रुवीकरण के अपने जांचे परखे हथियार को धार देने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक चुनावों में इस मुकाबले की पहली परीक्षा है। कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि हिंदुत्व और सामाजिक न्याय में कौन सा मुद्दा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भारी पड़ने वाला है।

आम तौर पर विरोधी के हमले को उसके खिलाफ अपना हथियार बना लेने की कला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज की राजनीति में सबसे ज्यादा सिद्धहस्त माना जाता है और उनकी लगातार सियासी कामयाबी का यह बड़ा कारण है। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी कुछ वैसी ही राजनीतिक शैली अपनाते दिख रहे हैं। इसका पहला संकेत खुद राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव प्रचार में कोलार में चुनावी सभा में दिए गए उनके भाषण से मिला है, जिसमें उन्होंने सरकार और शासन प्रशासन में पिछड़ों दलितों और आदिवासियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हुए उनकी बेहद कम हिस्सेदारी पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अपने

भाषण में राहुल ने पिछड़ों के बेहद कम हिस्सेदारी के आंकड़े देते हुए पूछा कि साफ जाहिर है कि पिछड़ों का अपमान कौन कर रहा है।

राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने के लिए जातीय जनगणना की मांग पर जोर देते हुए कहा कि सरकार 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करे। राहुल ने अपने भाषण के जरिए एक तरफ भाजपा द्वारा 2019 में कोलार में ही दिए गए उनके भाषण के मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी, जिसे लेकर उन्हें सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है, पिछड़े वर्ग के अपमान से जोड़ने का जवाब देकर खुद को पिछड़े वर्गों के सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में खड़ा कर दिया है और भाजपा के हिंदुत्व के जवाब में पिछड़ों की हिस्सेदारी के मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष का नया सियासी हथियार बनाने के संकेत दिए हैं। राहुल सिर्फ कोलार में ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कर्नाटक के बीदर की चुनावी सभा में भी यही मुद्दा उठाया और सोशल मीडिया के जरिए भी पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हिस्सेदारी बढ़ाने का सवाल खड़ा कर दिया है।

राहुल के इस सुर के साथ जनता दल(यू), डीएमके, राजद, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने भी अपना सुर मिला दिया है। बिहार में पहले से ही नीतीश सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना शुरू कर दी है और जद(यू) राजद ने इसे अपना मुख्य मुद्दा बना रखा है। समाजवादी पार्टी भी इसे पुरजोर तरीके से उठा रही है। एनसीपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बसपा भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी के लिए जातीय जनगणना को जरूरी बताते हुए हाल ही में तमिलनाडु में समान विचार वाले दलों का एक सम्मेलन भी बुलाया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पिछड़ी जातियों की जनगणना कराने की मांग की है। अब कर्नाटक में हर चुनावी सभा में खरगे और राहुल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कर्नाटक के चुनावी महाभारत में भाजपा के हिंदुत्व बनाम कांग्रेस के सामाजिक न्याय के मुकाबले की परीक्षा है। नतीजा यह तय करेगा कि आगे कौन भारी पड़ेगा।

कर्नाटक के चुनावों से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। इस चुनाव में जीत उसके लिए आगे के चुनावों का दरवाजा खोलेगी और अगर हार हुई तो कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो जाएगी। क्योंकि कहावत है कि पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में यह कहावत थोड़ी अलग कुछ ये हो जाती है कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना और कांग्रेस में भले ही शीर्ष स्तर पर गांधी परिवार की जगह मल्लिकार्जुन खरगे अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन शीर्ष स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया अभी भी नहीं बदली है। जरूरी फैसले न लेने वाली जड़ता बरकरार है। रायपुर महाधिवेशन को दो महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन पार्टी की शीर्ष संस्था कार्यसमिति का गठन अभी तक नहीं हुआ। संगठन में खरगे अभी तक अपनी नई टीम नहीं बना सके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संसद में उनके सरकार पर बेहद आक्रामक तेवर और सूरत की अदालत से उन्हें मानहानि के मामले में सजा होने और उसके फलस्वरूप उनकी लोकसभा की सदस्यता का खात्मा और सरकारी आवास खाली करने के नोटिस से जो माहौल बना, कांग्रेस नेतृत्व में शीर्ष स्तर पर जड़ता अनिर्णय और सियासी संकट प्रबंधन की कमी से उसका फायदा होता नहीं दिख रहा है। दक्षिण भारत जहां से 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को सबसे ज्यादा सफलता की उम्मीद है और पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि इसकी शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनावों से हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों दक्षिण भारत के ही तीन नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।

आंध्र प्रदेश जहां कांग्रेस के पास अभी भी कार्यकर्ता और जनाधार तो है, लेकिन कोई नेता नहीं है, वहां उसके पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी पार्टी छोड़ दिए हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ ही केरल में कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जो राज्य कांग्रेस में सोशल मीडिया के प्रमुख थे, भाजपा में शामिल हो जाते हैं लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के माथे पर बल नहीं है। इसके फौरन बाद स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाती केशवन भी भाजपा में चले गए। लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेताओं जिनमें इन राज्यों के प्रभारी भी शामिल हैं, का आश्वस्ति भाव देखते बनता है। पार्टी के किसी नेता से बात कीजिए, तो दो तरह के जवाब मिलते हैं। एक खेमा जो राहुल गांधी का वफादार है उसका कहना है कि यह कांग्रेस का संकट काल है और इसमें जो पार्टी के साथ है वही सच्चा कांग्रेसी है और जो कमजोर लोग हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो जाएं। दूसरे वो नेता हैं जो इंदिरा राजीव और सोनिया के जमाने से राजनीति में हैं, वह निराशा के भाव से कहते हैं कि यह बेहद चिंता का विषय है कि नेतृत्व के पास इस तरह का मौसमी पलायन रोकने की न नीति है, न नीयत और न ही कोई ऐसा नेता जो संकट प्रबंधन में सिद्धहस्त हो और जाने वालों को रोक सके। हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता और कई बार के सांसद व विधायक नंदकुमार साय के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से राज्य के कांग्रेसी उत्साहित हैं, लेकिन ये कमाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व की कोई बडी भूमिका नहीं है।

अब सवाल है कि क्या कर्नाटक चुनावों के बाद कांग्रेस की रीति नीति और शैली में कोई बदलाव आएगा। क्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, प. बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार जैसे उन राज्यों जहां कांग्रेस की हालत खस्ता है, के लिए कांग्रेस नेतृत्व कोई नई रणनीति तैयार कर सकेगा। सवाल है कि साल के अंत में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनके लिए कांग्रेस के पास कोई नई कारगर रणनीति होगी या सब कुछ यथास्थितिवाद के ही भरोसे रहेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव के झगड़े को नया नेतृत्व कैसे हल करेगा। इन और कई सवालों का जवाब शायद कर्नाटक चुनावों के बाद कांग्रेस खोज सके पार्टी कार्यकर्ताओं इसकी बहुत उम्मीद है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

संन्यासोपनिषद

यह उपनिषद् सामवेद से सम्बद्ध है। इसमें कुल दो अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में संन्यास क्या है? कैसे ग्रहण किया जाता है ? उसके लिए कैसा आचार-व्यवहार होना चाहिए आदि का विशद वर्णन है। दूसरा अध्याय काफी बड़ा है। इसकी शुरुआत साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व) से की गई है। संन्यास का अधिकारी कौन है? इसकी विस्तृत गवेषणा की गई है। संन्यासी का भेद बताते हुए 1. वैराग्य संन्यासी 2. ज्ञान संन्यासी 3. ज्ञान-वैराग्य संन्यासी और 4. कर्म संन्यासी की विस्तृत व्याख्या की गई है। आगे चलकर छः प्रकार के संन्यास का क्रम उल्लिखित हुआ है- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत इसी क्रम में आत्मज्ञान की स्थिति और स्वरूप का भी वर्णन उपनिषद्कार ने कर दिया है। संन्यासी के लिए आचरण की पवित्रता और भिक्षा में मिले स्वल्प भोजन में ही संतुष्ट होने का विधान बताया गया है। उसे स्त्री, भोग आदि शारीरिक आनन्द प्राप्ति से दूर रहने का निर्देश है। इस प्रकार आहार-विहार का संयम बरतते हुए नित्य प्रति आत्म चिन्तन में तल्लीन रहना चाहिए। ऊंकार का जप करते रहना चाहिए इसी से उसके अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रकाश प्रकट होता है और वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनता है।

अब संन्यास उपनिषद् का वर्णन करते हैं। क्रमानुसार नश्वर जगत् का परित्याग कर देने वाला विरक्त ही संन्यासी होता है। (प्रश्न) संन्यास किसे कहते हैं? संन्यासी किस तरह का होता है ? (उत्तर) संन्यासी वह है, जो आत्मा के उत्थान हेतु माता-पिता, स्त्री-पुत्र, बान्धव आदि के द्वारा अनुमोदित पूर्व में कही क्रियाओं का परित्याग कर देता है; जो हमेशा की तरह ऋत्विजों को नमन वंदन करने के पश्चात् वैश्वानर यज्ञ सम्पन्न करता है। इस पुनीत अवसर पर यजमान अपना सभी कुछ दान कर दे तथा ऋत्विज् सम्पूर्ण सामग्री को पात्रों समेत हवन कर दे। संन्यासी द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्नियों तथा सभ्य (वैदिक कालीन अग्नि) एवं आवसथ्य (स्मृतिकालीन अग्नि) को प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान पाँचों वायुओं में आरोपित करना चाहिए। शिखा (चोटी) सहित सभी केशों का मुण्डन करा देना चाहिए। यज्ञोपवीत को त्याग दे एवं पुत्र को देखकर इस तरह कहे कि तुम यज्ञ रूप हो, सर्वस्वरूप हो। यदि पुत्र न हो, तो वह अपनी आत्मा को ही लक्ष्य करके उपदेश देकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर गमन कर जाए।

क्रमशः ...

सिंधुताई सपकाल महाराष्ट्र की मदर टेरेसा

सिंधुताई सपकाल महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से मशहूर हैं। 1200 से भी अधिक अनाथ बच्चों की माँ बनने वाली सिंधुताई ने बेसहारा होने का दर्द खुद महसूस किया था। 10 वर्ष की छोटी सी अवस्था में अपने से लगभग 21 वर्ष बड़े पुरुष से विवाह होने के कुछ समय बाद गाँव के एक व्यक्ति के कहने पर उनके पति ने गर्भावस्था के अंतिम चरण में उन्हें घर से निकाल दिया। माता-पिता ने भी जब आश्रय देने से मना कर दिया तो जानवरों के तबेले में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। उस असहाय स्थिति में जीवनलीला समाप्त करने का विचार भी आया मगर आत्महत्या का विचार त्याग कर संघर्ष करने का फैसला किया। अब चार दशक से भी अधिक समय से सिंधुताई अनाथ और बेसहारों को आश्रय दे रही हैं।

आज उनके परिवार में 250 से अधिक दामाद, 50 बहुएँ और 1000 से भी अधिक नाती-पोते हैं आज भी माई अपने इन बच्चों के लालन-पालन के लिए निरंतर संघर्षरत है। सिंधुताई पारंपरिक मराठी वेषभूषा में बड़ी सी लाल बिंदी माथे पर लगाए हुए सभाएँ करके अपने भाषण में अनाथ बच्चों व निराश्रित महिलाओं के लिए स्थापित आधा दर्जन से भी अधिक आश्रमों के बारे में बताते हुए मदद के लिए आँचल फैला देती है और देखते ही देखते माई के हजारों बच्चों के लिए हर तरफ से रुपए-पैसे से लेकर खाने-पीने की चीजें सौंप दी जाती है। पिछले लगभग दो महीनों से लॉकडाउन के कारण सिंधुताई का कहीं आना-जाना नहीं हो पा रहा है।

वे बताती हैं, लॉकडाउन के कारण भाषण बंद हैं और भाषण बंद तो राशन बंद है। इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन हम डटे हैं। सिंधुताई ने 20वीं सदी के सातवें दशक में महाराष्ट्र के नवर गाँव में महिलाओं को इकट्ठा कर उनके द्वारा जंगल से एकत्र किए गए गोबर की कीमत वन विभाग से सीधे उन्हें ही दिलवाकर पहली लड़ाई जीती थी। सिंधुताई के आश्रम महाराष्ट्र के शहरों से लेकर गाँवों तक फैले हुए हैं।

सिंधुताई के इस विशिष्ट कार्य हेतु उन्हें अब तक देश-दुनिया के करीब सात सौ से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी इस संघर्षमय जीवनगाथा से प्रेरित होकर फिल्मकार अनंत महादेवन ने वर्ष 2010 में %मी सिंधुताई सपकाल% नाम से फीचर फिल्म भी बनाई थी। वे कहती हैं, %मैं श्रीकृष्ण को जन्म देने वाली देवकी नहीं हूँ, मैं तो आज भी अनाथ बच्चों के लिए यशोदा बनने का प्रयास कर रही हूँ।%

आकांक्षाओं के बीच भारत में एससीओ बैठक का मतलब

केएस तोमर

मौजूदा यूक्रेन युद्ध में युद्धविराम या समाधान की जरा भी उम्मीद न होने की पृष्ठभूमि में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की दो दिवसीय बैठक आज से गोवा में शुरू हो रही है, जिसमें सदस्य देशों को सुरक्षा मुद्दे जैसे क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, वैश्विक खाद्य और सुरक्षा मुद्दे से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर विचार करने की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रत्येक सदस्य देश की संप्रभुता को बनाए रखने की खातिर संघर्षों को टालने के लिए सख्त जरूरी है।

भारत के नजरिये से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बैठक में उपस्थिति की पुष्टि सकारात्मक कदम है और यह घटना 2011 से आपस में न मिलने वाले दो सदस्य देशों के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम कर सकती है। विदेश नीति विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान के रवैये में बदलाव के पीछे चीन का हाथ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चीन और रूस एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के मुताबिक, हाल के वर्षों के घटनाक्रम के कारण वैश्विक सुरक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि एससीओ क्षेत्र भी इन चुनौतियों से प्रभावित है और एससीओ चार्टर सदस्य देशों से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान का आह्वान करता है। यदि योजना के अनुसार सब कुछ ठीक रहा, तो पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की यात्रा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की भावी दिल्ली यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, क्योंकि उन्हें निमंत्रण दिया गया था, जिसका जवाब नहीं आया है।

एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका गठन 18 जून, 2001 को किया गया था और जो सदस्य देशों के बीच

आपसी विश्वास को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य व्यापार, राजनीति, शोध, अर्थव्यवस्था, तकनीक, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति आदि को बढ़ावा देना है।

एससीओ बैठक की तैयारी एक बोझिल कवायद है, जिसमें रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और पर्यावरण मंत्रियों जैसे नौ देशों के अन्य मंत्रिस्तरीय प्रमुख भी व्यापक चर्चा करेंगे, जो एससीओ सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए मार्च, 2023 से शुरू हुई थी। विश्लेषकों का कहना है कि एससीओ सदस्य सितंबर, 2022 की बैठक के प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र एवं दुनिया के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों पर विचार करेंगे। यह निश्चित है कि सदस्य देश नशीले पदार्थों के खतरे, कट्टरवाद, मानव संकट और तालिबान शासन की महिला विरोधी मानसिकता, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर और तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

भारत पड़ोसी पहले की अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध बनाए रखने का इच्छुक है। भारत हमेशा से यह कहता आ रहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा है, तो उसे हिंसा और आतंकवाद से मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाएगा।

भारत दवारा गोवा में होने वाली एससीओ बैठक का निमंत्रण दिए जाने पर पाकिस्तान असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि इसे अस्वीकार करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब होती। इससे वह चीन भी नाराज हो सकता था, जो रूस के साथ एससीओ का संस्थापक सदस्य है। लेकिन बैठक में भाग लेने पर पाकिस्तान के वे कट्टरपंथी नाराज हो सकते हैं, जो कभी भी दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य नहीं होने देना चाहते। बारह वर्षों के अंतराल के बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है।

विशेषज्ञों की राय है कि एससीओ को न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है, जो विवादों को दूर कर सके। एससीओ और ब्रिक्स के संयोजन से इंटरबैक कंसोर्टियम (जो अभी परिकल्पना ही है) साझा वित्तीय निधियों की कमी की समस्या को दूर कर सकता है। एससीओ एकमात्र संगठन है, जो आंतरिक मतभेदों के बावजूद मौजूदा विश्व व्यवस्था में कुछ हद तक अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। यह उस मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो प्रत्येक सदस्य संगठन में रखता है। और उनके हितों के टकराव को देखते हुए यह हाल के दिनों में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ब्रेजिंस्की सिद्धांत के अनुसार, जो देश मध्य एशिया पर हावी है, वह यूरेशिया पर हावी है, और जो यूरेशिया पर हावी है, वह दुनिया पर हावी है। एससीओ के गठन के बाद से ही चीन और रूस ने इस पर ध्यान दिया है। शंघाई फाइव ने वास्तव में मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य देशों में हस्तक्षेप का विरोध किया।

विशेषज्ञों का कहना है कि एससीओ की सदस्यता क्षेत्रीय एकीकरण हासिल करने, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और सीमा पार स्थिरता को मजबूत करने में योगदान दे सकती है, जो पहले से ही खतरे में है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और एससीओ कूटनीति के माध्यम से बढ़ती मांग पूरी की जा सकती है। एससीओ सदस्यों के साथ तापी, आईपीआई (ईरान-पाकिस्तान-भारत) जैसी रुकी हुई परियोजनाओं पर बातचीत से इसमें गति आ सकती है।

इसी तरह एससीओ मध्य-एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत और मध्य एशिया के बीच आने वाली व्यापार बाधाओं पर काबू पाया जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भारत को दूरसंचार, आईटी, बैंकिंग, वित्त और दवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मध्य एशियाई देशों में एक बड़ा बाजार बनाने का अवसर मिलता है। भू-राजनीतिक रूप से, एससीओ अपनी %कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी% को लागू करने के लिए एक बाजार प्रदान करता है, क्योंकि मध्य एशिया विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है।

चीन और पाकिस्तान पर अंकुश लगाने के अलावा एशिया में अग्रणी भूमिका निभाने की भारत की आकांक्षा एससीओ के माध्यम से संभव हो सकती है, क्योंकि इसमें एससीओ के सह-संस्थापक के रूप में भारत का एक पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस शामिल है।

बापू की दिनचर्या

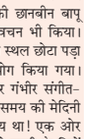

प्रातः कालीन प्रार्थना (भाग-4)

गतांक से आगे...

बापू के प्रत्येक प्रवचन में, उनके दीर्घकालीन अनुभवों के कारण अनेक स्मरणीय बातें रहा करतीं। बापू सत्याग्रहाश्रम में प्रार्थना के पश्चात् वहाँ जब सिर्फ आश्रमवासी रहते, उनके एक-एक प्रश्न पर यथा-सत्याग्रही के नाते उनका व्यवहार कैसा हो, इस पर प्रकाश डालते। उनके अनुसार सत्याग्रह मात्र अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का एक अस्त्र नहीं, बल्कि सत्याग्रह तो सत्य की खोज करनेवालों की संपूर्ण जीवन पद्धति है। इसीलिए जीवन के सभी पहलुओं की परीक्षा प्रार्थनास्थल पर सत्याग्रह की कसौटी पर होती। कई निजी सवालों की छानबीन बापू प्रार्थना के बाद करते। इसी स्थल पर उन्होंने गीता प्रवचन भी किया। दांडी यात्रा के समय लोगों की भीड़ की वजह से प्रार्थना स्थल छोटा पड़ा तो साबरमती नदी के विशाल रेती के तट का उपयोग किया गया। नारायण भाई देसाई के शब्दों में पंडित खरे की सागर गंभीर संगीत-ध्वनि, जो जड़ को भी दोलायमान करने वाली थी, उस समय की मेदिनी के सामने अपर्याप्त सिद्ध हुई। स्थल भी कितना रमणीय था! एक ओर हृदयकुंज दूसरी ओर दत्तमंदिर, तीसरी ओर वह नदी जो गरमी के दिनों में अंतःस्रोता फल्गु की तरह रुश, रेतीली, तो वस्तु में तूफानी बाद के कारण करने वाली, किंतु चारही गारा प्रार्थना स्थल का चरण प्रक्षालन करते हुए अखंड बहती हुई नदी बापू उत्तर की ओर पेड़ के नीचे बैठते और उनके दोनों ओर भाई बहनें प्रातःकाल की प्रार्थना में जापानी बौद्ध मंत्र, उपनिषद् मंत्र, प्रातःसम वाले श्लोक, एकादश व्रत, कुरान की आयतें, जरथोस्ती (पारसी) भजन, धुन और गीतापाठ - यह क्रम था। गीता का नित्य पाठ इस क्रम के होता कि एक सप्ताह में संपूर्ण पारायण हो जाए। पहले दो सप्ताह में पूरी गीता पढ़ी जाती। काका साहब के सुझाव से यह क्रम एक सप्ताह में पूरा होने लगा। तदनुसार शुक्रवार को पहला दूसरा शनिवार को तीसरा, चौथा और रविवार को ही सातवीं आठवीं सोमवार को नव दस ग्यारह बारहवाँ, मंगलवार को तेरहवीं, चौदहवाँ, पंद्रहवा बुधवार को सोलहवाँ- सत्रहवाँ और गुरुवार को अट्ठारहवां-यह क्रम चलता। साप्ताहिक गीता-पारायण में अध्यायों का यह विभाजन विनोबाजी ने किया था। इसके अतिरिक्त माता कस्तूरबा के निधन-दिवस पर हर महीने की बाईसवीं तारीख को विशेष रूप से संपूर्ण गीता का पारायण होता। आगा खाँ महल से छूटने के बाद, सेवाग्राम में बापू की सुबह की प्रार्थना में संस्कृत गीता के बदले गीताई का पारायण होने लगा, जो विनोबाजी की कृति है।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

स्वर्ण जयंती समारोह कल, राज्यपाल बैस रहेंगे मुख्य अतिथि

रायपुर। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सरस्वती विहार रोहणीपुरम रायपुर में 6 मई को स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत, समाज सेवक बसंत अग्रवाल, सरस्वती शिक्षा संस्थान प्रादेशिक सचिव विवेक सक्सेना, मां सरस्वती बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बीके दानी एवं सचिव प्रकाश सिंह ठाकुर समेत प्राचार्य, आचार्यगण एवं पूर्व विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल को उर्स पाक कार्यक्रम में शामिल होने का मिला न्यौता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में हजरत बाबा सौय्यद अब्दुर्रहमान शाह काबुली कमेटी के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को 26 मई को दुर्ग में आयोजित सालाना उर्स पाक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश देशलहरा, जनरल सेक्रेटरी श्री रऊफ कुरैशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

वन विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद वन विभाग ने सहायक ग्रेड-3 के रिक्त 19 पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया है। राज्य शासन के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ अनिल राय ने बताया कि इसके अनुपालन में संघ द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। आकाश सिंह राजपूत, चंद्रशेखर वर्मा, नारायण दत्त, राहुल वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर अटल नगर में नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से अभिनेष खरे को जिला लघु वनोपज संघ जगदलपुर, वीरेन्द्र वर्मा को जिला लघु वनोपज सहकारी संघ नारायणपुर, सुश्री मधुलिका साहू को कांकेर, सुश्री श्वेता साहू को केशकाल तथा सुजीत कुमार को बीजापुर में नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 159 कोरोना मरीज मिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। यहां दिनों दिन अब कोरोना पर लगाम लग रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 159 नए कोरोना मरीज आए है। वहीं, 4,330 सैम्पलों की जांच हुई है। आपको बता दें कि सात कोरोना पीड़ित हॉस्पिटल से व 388 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं। आज किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,445 हो गई है।

कांग्रेस नेता पर बाइक सवार युवकों ने किया हमला, लूटपाट का प्रयास

रायपुर। पुरानीबस्ती थाना क्षेत्र के शांति चौक के पास बीती रात एक कांग्रेस नेता पर बाइक सवार युवकों ने हमला कर लूटपाट का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता सुरेश ठाकुर कल रात अपने परिजनों के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उनकी कार के शीशे पर ठंडे से वार किया। श्री ठाकुर संभल पाते इसके पूर्व ही बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इससे सुरेश ठाकुर के कान के पास चोटें आई हैं। प्रार्थी के अनुसार बदमाशों ने उनके गले से सोने की चैन आदि छीनने का प्रयास किया। इसी बीच हो-हल्ला मचने पर तथा लोगों की भीड़ जमा होने पर आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण जांच में लेते हुए पतासाजी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानीबस्ती क्षेत्र के ही दो युवकों का नाम सामने आया है।

शंकरनगर और तेलीबांधा टैंकी से अब नहीं होगा लीकेज

रायपुर। तेलीबांधा और शंकरनगर के ओवरहेड टैंक में लीकेज हो गई थी, जिस वजह से स्वच्छ पेयजल व्यर्थ बह रहा था। लीकेज को खत्म करने तथा कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए कल शाम पेयजल सप्लाई के बाद आज सुबह शट डाउन कर रायपुर नगर निगम द्वारा रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ किया गया। जिस वजह से तेलीबांधा और शंकरनगर समेत खमतराई और भनपुरी ओवरहेड टैंक से जुड़े क्षेत्र आज प्रभावित रहे। इन जगहों पर कल सुबह से पहले की तरह पेयजल सप्लाई सुचारू हो जाएगी। निगम के फिल्टर प्लांट के प्रभारी अभियंता बद्री चन्द्राकर तथा नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि तेलीबांधा तथा शंकर नगर की टैंकीयों में लीकेज की समस्या थी। इनलेट पाइप में भी सुधार की आवश्यता थी। साथ ही मेन पाइप लाइन में भी तकनीकी दिक्कतें थी जिस वजह से तेलीबांधा और शंकर नगर समेत इससे जुड़े खमतराई और भनपुरी क्षेत्र के घरों में भी भरपूर मात्रा में पेयजल नहीं पहुंच पा रहा था। आज मरमत के बाद इन जगहों पर कल सुबह से भरपूर मात्रा में पेयजल पहुंचने लगेगा।

भूपेश सरकार युवाओं के लिये स्वर्णिम कालः कांग्रेस

रायपुर। भूपेश सरकार युवाओं के लिये स्वर्णिम काल है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सभी विभागो में भर्तीया निकाली जा रही है। अखबारो के पन्ने भर्तियों के विज्ञापनों और खबरों से भरे पड़े है। राज्य बनने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां निकली है। अभी तक लगभग 20 हजार से अधिक पदो के लिये भर्तियां निकल चुकी है। शिक्षा विभाग, राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम, पीडब्लूडी, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, आईटीआई तकनीकी शिक्षा, विद्युत कंपनी, वन विभाग में भर्तियां निकल चुकी है। शेष सभी भर्तियों में भर्तियां निकालने की तैयारी है।

देश के अन्य राज्यों तथा केन्द्र सरकार के विभागों में जहां भर्तियों का अकाल है भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में भर्तियों की बहार आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता है और उनका कमिटमेंट है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल से सरकारी विभागों में बंद भर्तीयो को उन्होंने ने शुरू किया था। हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण में कटौती के बाद एक गतिरोध की स्थिति आई थी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को बहाल किया मुख्यमंत्री ने फिर से भर्तियों के लिये अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री के इन्हीं प्रयासों के कारण राज्य की बेरोजगारी दर 1 प्रतिशत से कम है।

शुक्ला ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के 15 सालों तक युवाओं के लिये सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिया था। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेके पर नियुक्तियां होती थी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं के लिये सरकारी विभागों में सीधी भर्तियां निकाली गयी। पिछले साढ़े 4 सालों में सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक भर्तियां कांग्रेस सरकार ने किया। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता में युवाओं को रोजगार देना है। उनकी सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिये बेहतर योजना बनाकर कार्य किया। साढ़े 4 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिये। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं के सरकारी नौकरी में भर्ती के द्वार खोले गये। नियमित और अनियमित दोनों प्रकार की भर्तियां निकाली गयी।

राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से 2885 नौकरियां व्यापम के माध्यम से 4530 नौकरियां, 14580 शिक्षकों की भर्तियां, बिजली कंपनी में 3000 नौकरियां, स्वास्थ्य विभाग में 4000 नौकरियां, पुलिस विभाग में 8292 नौकरियां, राजस्व विभाग में 392 नौकरियां, वन विभाग में 3861 नौकरियां, महिला एवं बाल विकास विभाग में 800 से अधिक भर्तियां, 250,000 विभिन्न विभागों में नियमित भर्तियां की गयी, 44 विभागों में 3155 अनुकंपा नियुक्तियां, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज 1041 अन्य मेडिकल कॉलेजों में 230 नियुक्ति कृषि उद्यानिकी में 1200 नियुक्तियां इसके अलावा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भी शिक्षकों की भर्ती की गई। 147000 अनियमित को नियमित कर रोजगार दिया। यह तो सरकारी विभागों के रोजगार है। कांग्रेस सरकार ने 14 लाख परिवारों को वन के माध्यम से रोजगार से जोड़ा तथा 26 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया गया। 59175 बुनकरों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया। आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओ को रोजगार देने के लिये भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया हैं।

यूपी से बेहतर है छत्तीगसढ़ का परिणाम : मुख्य न्यायाधीश

बेमेतरा। आने वाली 13 मई को बेमेतरा जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जिला स्तर पर तैयारी की जा रहीं है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेमेतरा के जिला कोर्ट के जज व प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में आयोजित लोक अदालतों के पूर्व के आंकड़ों का अवलोकन करने से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालत के परिणाम की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में लोक अदालतों का परिणाम ज्यादा अच्छा और सराहनीय रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य पूरा हुआ है।

लोक अदालत की सफलता में सभी का सहयोग प्राप्त है और इस उददेश्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान जरूरी भी है, जिससे अच्छे परिणाम आ सकें। उन्होंने आगे कहा कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, ट्रैफिक चालान, कमर्शियल कोर्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद के मामलों का लोक अदालतो में निराकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छोटे-मोटे विवाद का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हो जाने पर न्यायालय पर ऐसे छोटे मामलों का भार कम होता है। न्यायालय को संगीन मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करने में सुगमता होती है। वर्चुअल बैठक में उपस्थित कलेक्टर व एसपी से अपेक्षा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास करें और इसके क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आती है तो सालसा के सदस्य सचिव से संपर्क करें।

महिला थाना चौराहा दे रहा दुर्घटनाओं को निमंत्रण

- आए दिन बेरिकेट की अजीबो गरीब सेटिंग के कारण लोग हो रहे परेशान

रायपुर। राजधानी में लगातार बढ़ती आबादी के कारण शहर का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां पर जाम की स्थिति निर्मित न होती हो। सिग्नल व्यवस्था फेल होने के कारण शहर के अनेक चौक चौराहों इन दिनों सुबह से शाम तक जाम की स्थिति का शिकार हो रहे हैं। शहर का प्रमुख मार्ग कटोरा तालाब से लाखेनगर चौक के बीच सड़कों की बेतरतीब खुदाई एवं महिला थाना चौक में बेरिकेटिंग के अजीबोगरीब व्यवस्था आए दिन दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। दोपहिया वाहन चालक अक्सर यहां पर चोटिल हो रहे हैं। शहर के प्रबुद्ध नागरिक शैलेंद्र मिश्रा, रोली शुक्ला, अशोक चंद्राकर एवं जया मिश्रा ने इसके लिए यातायात पुलिस एवं नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए परिवहन मंत्री मो. अकबर से तत्काल यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि शहर में इन दिनों जल मिशन के चलते पाइप को जोड़ने का कार्य भी लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है ठेकेदारों की लापरवाही के कारण शहर के मुख्य मार्गों में सड़कें ठीक से मरम्मत नहीं करने के कारण आते जाते समय जबर्दस्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली ऑफिस बूढ़ापारा से लेकर बूढ़ेश्वर मंदिर तक गणेश मंदिर के साइड में खोदे गये गड्ढे चौपहिया वाहन एवं दोपहिया वाहन को आरपार आसानी से नहीं जा पाते जिसके कारण उक्त स्थल पर सुबह शाम लंबा जाम लगता है। वहीं टाटीबंध चौक में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। रिंग रोड की हालत इससे भी ज्यादा बदतर है। सर्विस रोड पर बड़ी ट्रकों की वजह से आवाजाही प्रभावित होती है। वहीं ओव्हर ब्रिज के दोनों ओर विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ियों के कारण भी जाम की स्थिति देखी जाती है।

शिवरीनारायण कोई विकासखंड नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने दिया 30 बिस्तरों की सौगातः राजेश्री

शिवरीनारायण। भगवान शिवरीनारायण की पावन धरा में 30 बिस्तर के अस्पताल का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास ने क्षेत्रीय विधायक श्रीमती इंदू बंजारे, नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मनोज तिवारी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करते हुए राजेश्री महन्त महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन्होंने शिवरीनारायण क्षेत्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, वास्तव में 30 बिस्तर का अस्पताल विकासखंड स्तर पर ही संभव होता है ,शिवरीनारायण कोई विकासखंड नहीं है इसके पश्चात भी इसे इतना बड़ा सौगात प्राप्त हुआ है। भगवान शिवरीनारायण के सम्मान को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री ने नियमों का शिथिलीकरण करके यह कार्य किया है, इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है।

श्री स्वामी आनंताचार्य जी महाराज ने भूमि पूजन का कार्यक्रम विधि पूर्वक संपन्न कराया।

दानदाता परिवार से श्री बलदाऊ साव एवं श्रीमती रश्मि केसरवानी का मंच में विशेष रूप से स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेश्री महन्त ने कहा कि इस चिकित्सालय के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात यहां शिवरीनारायण सहित राज्य एवं देश -विदेश से आने वाले पर्यटकों की स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित समाधान हो सकेगा। उन्होंने इस अवसर पर दानदाता परिवार को सम्मानित करते हुए कहा कि शिवरीनारायण में चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए श्री प्रयाग प्रसाद केसरवानी जी के नाम पर उनके सुपुत्र श्री बलदाऊ साव ने जमीन दान किया था आने वाले समय में उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

पामगढ़ विधायक श्रीमती बंजारे ने कहा कि महन्त जी महाराज ने मुख्यमंत्री से शिवरीनारायण में स्वास्थ सुविधा के विस्तार के लिए इस अस्पताल की मांग रखी थी, इसका निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण अच्छे ढंग से हो ऐसी कामना करती हूं। लोगों को नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तिवारी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विशेष रूप से राघवेंद्र प्रताप सिंह, पप्पू बघेल, श्री सुखराम दास जी, राजेंद्र यादव, सुबोध शुक्ला, पिंटू भट्ट, शिव शंकर सोनी, निरंजन कश्यप, सरस्वती निषाद, राम चरण कर्ष, ईश्वरी निराला, देवा लाल सोनी, कमलेश सिंह, केशव नारायण सोनी, प्रतीक शुक्ला, तहसीलदार बजरंग साहू, डी के रावटे, हिमांशु तिवारी, हृदय अनंत, आशीष अग्रवाल, अजय केवट, गोपाल केवट, सोनू चौहान, पुरेंद्र सोनी, निर्मल दास वैष्णव, हर्ष दुबे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ,पुलिस प्रशासन सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे।

धान की खेती से हटकर किसान अपने खेतों में उगा रहे है दूसरी फसलें

रायपुर। कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ के किसान धान की फसल के अलावा दूसरी फसलों के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं के चलते किसान अब धान के बदले दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित हो रहे है। क्योंकि धान के अलावा अन्य फसलों को उगाने के लिए शासन छत्तीसगढ़ के किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस योजना से प्रोत्साहित होकर ग्राम बोन्दा विकासखण्ड पुसौर के किसान तेजराम गुप्ता ने अपने खेतों में सूरजमुखी फसल लगाकर दोहरा लाभ उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास कुल जमीन 4.130 हे. है। वे सभी में खरीफ में धान की खेती करते हैं एवं रबी में 2 हे. में धान की खेती करते थे। इस रबी मौसम में ग्रा.कृ.वि.अधि.एच.के.साहू द्वारा धान फसल के बदले में सूरजमुखी फसल के

बारे में बताया गया तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी से प्रभावित होकर उन्होंने 2 हे. में सूरजमुखी लगाने का निश्चय किया। कृषि विभाग से उन्हें बीज सुक्ष्म पोषक तत्व एवं कीटनाशक निःशुल्क प्रदाय किया गया। साथ ही उन्होंने 5 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट स्वयं से क्रय करके उपयोग किया।

किसान तेजराम गुप्ता ने बताया कि खेत की तैयारी के लिये 3 गहरी जुताई एवं 2 बार रोटावेटर से जुताई करके खेत तैयार किया गया।

बीज की बुवाई के समय वर्मी कम्पोस्ट को अच्छी तरह खेत में मिलाने के बाद बीज की लाईन से बुवाई किया गया। जिसमें इसके कुछ दिन पश्चात विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया एवं उचित सलाह दिया गया। जिसमें क्षेत्रीय ग्रा.कृ.विअधि. की सहभागिता निरंतर बनी रही। बीज बुवाई के 25-30 दिन बाद निंदाई गुडाई एवं मिट्टी चढ़ाने का काम किया गया। समय-समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई किया गया। इसमें धान की तुलना में बहुत की कम मात्रा में पानी की आवश्यकता हुई। कीट व्याधि के नियंत्रण के लिये क्लोरोपाईरीफास एवं एजाडिरेक्टीन 1500 पी.पी.एम.का छिड़काव किया गया। वर्तमान में फसल काटने योग्य हो चुका है एवं फसल की उपज काफी अच्छी हुई है। उन्होंने बताया कि इस फसल से काफी मात्रा में लाभ होने की उम्मीद है। किसान श्री तेजराम गुप्ता द्वारा सूरजमुखी की फसल अपनाने में उनकी आय में वृद्धि होगी एवं फसल चक्र होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ खेती की वैज्ञानिक विधियों को किसानों के द्वारा अपनाया जा रहा है।

बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

बाल अधिकारों की रक्षा में युवाओं की सक्रिय भूमिका-तेजकुंवर

रायपुर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने कहा है कि बाल अधिकारों की रक्षा में युवाओं की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है। उन्होंने नशामुक्ति, मोबाईल की लत और अन्य कई सम-सामयिक मुद्दों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए विद्यार्थियों से भारतीय समाज की आदर्श परंपराओं का पालन करने की अपील की। वे आज यहां एमिटी युनिवर्सिटी रायपुर के सभागार में गुरुवार को बाल अधिकारों के संरक्षण पर आहवान नामक जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थीं।

वाईस चांसलर डॉ. पीयूष कांत पाण्डेय ने कहा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जागरूकता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने छात्रों से बाल अधिकारों को समझ कर बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अपील की। आयोग के सचिव श्री प्रतीक खरे द्वारा बाल अधिकारों का महत्व, अधिकार आधारित दृष्टिकोण बनाये रखने तथा बच्चों के अधिकार व प्रचलित कानूनों पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने छात्रों को बच्चों से बात करने और उनकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास आदि को विकसित करने के तरीके भी बताए।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वाईस चांसलर प्रोफेसर डॉ. पीयूष कांत पाण्डेय और आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पाटले सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। बाल अधिकार पर कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के भाषा, फैशन और मनोविज्ञान विभाग द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में विधि, मीडिया तथा संचार विभाग ने सक्रियता के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम में युनिवर्सिटी ने बाल अधिकार के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रो वाईस चांसलर डॉ. सुरेन्द्र रहमतकर, प्रो. डॉ. बोधिसत्व आचार्य डायरेक्टर विधि विभाग, प्रो. डॉ. इंद्राणी सिंह राय तथा अन्य फैकल्टी मेम्बर उपस्थित थे।

मेयर को जानकारी ही नहीं और हो गया 27 करोड़ का घोटाला

रायपुर होर्डिंग स्कैम : बिफरे ढेबर, बोले एफआईआर करेंगे

रायपुर। राजधानी रायपुर में करोड़ के घोटाला का मामला सामने आया है। नगर निगम रायपुर में होर्डिंग घोटाला हुआ है। नगर निगम के अफसरों ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अफसरों ने एड एजेंसियों से पैसे लिया फिर मन चाहे पोल लगवाकर होर्डिंग लगवाने का काम किया है। बड़ी बात तो यह है कि रायपुर स्थित माता सुंदरी स्कूल के सामने चौराहे बनवा दिया है। इसकी जानकारी पार्षद, कलेक्टर, विधायक और निगम के महापौर को भी नहीं है।

इस घोटाले को महापौर एजाज ढेबर ने पकड़ा है। उन्होंने कहा कि बिना पूछे बिना जानकारी के अधिकारियों ने होर्डिंग के टेंडर के लिए दे दिया गया है। एजेंसी को मनचाहे रेट दिए है। वन रहे चौक के बारे में बताया कि इसे किसने बनाया और कौन काम कर रहा है,कुछ पता नहीं है। उसके खोजबीन जारी है। अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें भी अफसरों के मिलीभगत हो सकती है। इस विषय पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। अफसरों ने महापौर से छुपाकर 27 करोड़ रुपए का घपला किए है। इसे लेकर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि घोटाला करने वाले अफसरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी की जाएगी। अपसारो

के नाम पर एफआईआर दर्ज होगा और बन रहे चौक को तोड़ने के आदेश दिए।

महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि 7 लोगों की समिति बनाई गई है जिसमें मैं भी शामिल हूं। अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 27 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि महापौर होने के नाते मैं चाहता हूं कि निगम का राजस्व में बढ़ोत्तरी हो, लेकिन इस तरह से नहीं। अफसरों ने एड एजेंसियों के अनुसार काम किया है। इस घोटाले में जो भी शामिल है। उन्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शा जाएगा। महापौर एजाज ढेबर ने गुरुवार को एमआईसी की बैठक ली। बैठक में ढेबर ने कहा- जांच करने से पता चला है कि जो होर्डिंग्स लगाई गई है वो धांधली है। मन चाहे टेंडर दिया गया है। 15 बाय 9 की साइज को 18 बाय 18 किया गया है। जैसे रेट लगा वैसे नहीं लगना था। एमआईसी में रेट फाइनल करने का प्रस्ताव भी नहीं आया। उन्होंने कहा की शहर में लगे होर्डिंग अवैध है।

एक प्रश्न पर महापौर ने कहा- जो बचते रहता है वो सही है जो पकड़ा गया वही चोर है। बहुत दिनों से ये घोटाला चल रहा था। आखिरकार अब पकड़ में आ ही गया। 20 दिन तक स्टडी करने करने के बाद पता चला कि कागजों में घुमाकर काम किया गया है। इस विषय में मैंने 4 एक्सपर्ट लोगों से बात की और दो लोग बाहर से बुलाए, तब पता चल पाया कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जो 27 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। महापौर ने कहा कि यदि मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो लोकायुक्त में जाउंगा, ये मामला शहर की सुरक्षा के लिए है। जो भी अफसर होंगे उनके निलंबन होगा और एफआईआर होगी। रात में ही चौक बन गई जिसकी खबर किसी को नहीं है। उसे भी तोड़ा जायेगा। कार्रवाई की जाएगी।

टूटे तो बहुत ही चुभते हैं, क्या कांच, क्या ....

देश के एक प्रमुख,अविभाजित मप्र, छग के सबसे बड़े आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने लगभग 50 साल तक रहने के बाद जनसंघ, भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, यह भाजपा के लिये बड़ा झटका है। उनका कहना है भाजपा,अटल-आडवाणी की पार्टी अब नहीं रही....? भाजपा में उपेक्षा का भी उनका आरोप है। सच्चाई यह है उनकी राजनीतिक राह में साजिश रची गईं...। 1977 में दो आदिवासी साय और ननकी राम कंवर पहली बार विधायक बने थे। साय 85,98 में भी विधायक बने वहीं 89 और 96 में रायगढ़ से लोस सांसद तथा 2009में राज्यसभा सदस्य बने तो 2017 में अनुसूचित जनजाति आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष बनाये गये थे। मप्र तथा छग के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पर बाद में उन्हें छग भाजपा की कोर कमेटी से भी हटा दिया गया। उन्हें छग राज्य बनने के बाद पहला नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अजीत जोगी के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले नंद कुमार साय को साजिश कर छग के पहले विस चुनाव में मरवाही में तब के सीएम अजीत जोगी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया गया,वे चुनाव हार गये। यदि वे अपनी सीट तपकरा से लड़ते,जीतते तो छग के सीएम भी बनते....! चुनावी इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि सीएम के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष को चुनाव लड़ाया गया हो...? खैर बाद में भाजपा की छग में 15 साल सरकार रही पर ये उपेक्षित रहे, इनको लोस प्रत्याशी भी नहीं बनाया गया, हाँ 2009 में राज्य सभा सदस्य बनाया गया,उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)का अध्यक्ष बनाया गया,उस पद से हटने के बाद उनकी उपेक्षा का दौर जारी रहा...साय के भाजपा छोड़ने के पीछे वजहें जो भी रही हों,यह तय है कि भाजपा के लिए अब चुनावों में कठिनाइयां बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासियों की है।और कुल 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार भाजपा को आदिवासी इलाकों में एक भी सीट नहीं मिली थी, तो इस बार भी जीत के आसार दिख नहीं रहे....? बल्कि विधानसभा के बाद लोस चुनावों में भी भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। साय के कांग्रेस प्रवेश से अब बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस को जो मुश्किलें पेश

आ रही हैं, उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है, यानी कांग्रेस के लिए, दोनों तरह से जीतने वाली स्थिति है, बशर्ते वह साय जैसे वरिष्ठ और जमीन से जुड़े राजनेता का सही इस्तेमाल राज्य और आदिवासियों के हित में करे...? हाँ नंद कुमार साय अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, वैसे वे लोकसभा के लिये भी एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं।

रोजगार का रास्ता सुको ने किया साफ

सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगी हाईकोर्ट की रोक को हटाते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। इससे सरकार को आरक्षण के तौर पर नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है।

उल्लेखनीय है कि आरक्षण के इस मुद्दे के कारण विगत वर्षों से सरकारी पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। यहां पर यह बताना भी लाजमी है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया था कि अखबारों में अब नौकरी के भर्ती विज्ञापन ही दिखाई देंगे और भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को एक बल मिला है।वैसे विस से सर्व सम्मति से आरक्षण का प्रस्ताव पूर्व राज्यपाल के समय से ही राजभवन में लंबित है नये राज्यपाल इस पर निर्णय लेंगे ऐसा लगता तो नहीं है।

विस, लोस चुनाव अमिताभ ही कराएंगे...

छग में मुख्य सचिव अमिताभ का कार्यकाल 2025 तक रहेगा वैसे अभी के हालात में यह तय माना जा रहा है कि अगला विस और लोस चुनाव वही करवाएंगे।छग में 89 बैच के आईएएस अमिताभ जैन का नंबर वरिष्ठता में सबसे उपर आता है वे अपने बैच के अकेले अफसर हैं। उनके बाद 90 बैच का कोई आईएएस छग में नहीं है। 91 बैच की आईएएस रेणु जी पिल्ले हैं तो 92 बैच के हैं सुब्रत साहू।अभी दोनों ही एडीशनल चीफ सेक्रेटरी हैं।वहीं इनके बाद 93 बैच के आईएएस अमित अग्रवाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में हैं। इसके बाद 94 बैच की रिचा शर्मा, निधी छिब्बर, विकासशील और मनोज पिंगुआ हैं जिनमें मनोज पिंगुआ को छोड़कर बाकी तीन को केंद्र सरकार ने एडीशनल सेक्रेटरी इम्पेनल किया है,वैसे अमिताभ और रेणु पिल्ले केंद्र में एडीशनल सेक्रेटरी इम्पेनल पहले ही हो चुके हैं वहीं अमित अग्रवाल एडीशनल सेक्रेटरी के तौर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। खैर 94 के बाद 95 बैच की मनिंदर कौर,गौरव द्विवेदी है इसके बाद 97 बैच की निहारिका बारिक हैं। 98 बैच के सुबोध कुमार सिंह हैं।99 बैच के सोनमणी वोरा का नंबर आता है। इसके बाद 2001 बैच की शहला निगार, 2002 बैच के डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं डॉ. रोहित यादव हैं। 2003 बैच की ऋचा सेन, सिद्धार्थ कोमल परदेशी, 2004 बैच की पी. संगीता, आर. प्रसन्ना, अमित कटारिया, अवलंगन पी,अलरमेल मंगई डी का नंबर आता है। बहरहाल अमिताभ 2025 में रिटायर होंगे।

निज़ात अभियान को बिलासपुर में अच्छी सफलता....

अवैध नशे के खिलाफ कार्यवाही और जागरूकता अभियान 'निजात' के तहत सिर्फ तीन माह के दौरान ही एनडीपीएस व आबकारी में ताबड़तोड़ कार्यवाही में कुल 1733 प्रकरणों में 1845 लोग गिरफ्तार किये गये जिसमे गैर- जमानतीय प्रकरणों में 301 आरोपी जेल भेजे गए हैं।बिलासपुर के एसपी संतोष सिंह के अनुसार निजात का असर अपराध में कमी के रूप में दिखा है। तीन माह और पिछले वर्ष की इसी अवधि के अपराधों की तुलना की गई तो पाया गया कि आईपीसी के कुल अपराधों में 10 फीसदी, चाकूबाजी में 79 प्रतिशत, मारपीट में 12 प्रतिशत, छेड़छाड़ में 34 फीसदी और चोरी व नकबजनी में 15 प्रतिशत कमी आई है। यद्यपि कुल अपराधों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर 3692 अपराध दर्ज हुए है, जो की मुख्यतः एनडीपीएस और आबकारी में बढ़ी कार्यवाहियों की वजह से हैं।

और अब बस

0 बजरंगदल को बजरंगबली से जोड़ने वालों पर तरस ही आता है...?

0 विहिप के बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुत्व की दिशा में छग में भूपेश बघेल सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा कुछ भाजपाइयों को रास नहीं आ रही है।

07 वरिष्ठ आईएफएस अफसरों को नजरअंदाज कर श्रीनिवास राव को छग वन विभाग का मुखिया बनाया गया है।

यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड 2023 से सम्मानित हुए युवा वैज्ञानिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह में दो दिवसीय 18 वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का 04 मई को समापन हुआ। इस समारोह में 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड- 2023 प्रदान किया गया। इसके साथ ही इन युवा वैज्ञानिकों को 21 हजार रूपए पुरस्कार राशि, मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साइंटिस्ट अवॉर्ड से सम्मानित युवा वैज्ञानिक को किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षणिक समिति, एनसीईएसएसई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार डॉ. ललित शर्मा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. एस कर्माकर सहित वहां मौजूद समस्त वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने इन युवा वैज्ञानिकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

कनेक्टिविटी ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है - संतोष पांडेय

■ रावघाट रेल परियोजना की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के विकास की नई गाथा लिखेगा

रायपुर। भाजपा बस्तर संभाग प्रभारी एवं सांसद संतोष पांडेय ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रावघाट परियोजना पर कार्य जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने आश्वस्त किया है।

श्री पांडेय ने कहा कि कनेक्टिविटी से ही सब प्रकार का विकास संभव है। इसलिए बस्तर में जो रुके हुए काम हैं, वह पूर्ण हों, इस दिशा में भाजपा ने रेलमंत्री को अवगत कराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय को गंभीरता से लिया।

सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के महामंत्री केदार कश्यप और मेरी संभाग के प्रभारी होने के नाते रेल मंत्री के साथ भेंट में लंबी चर्चा

हुई। रेल मंत्री ने वहां की संभावनाओं को देखते हुए रावघाट रेल परियोजना को पूरा करने के लिए आश्वासन ही नहीं, बल्कि सीधा-सीधा आदेश दिया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है रावघाट परियोजना के शेष 140 किलोमीटर कार्य की जल्द ही शुरुआत होगी। अब दोनों तरफ से काम चालू होगा, जगदलपुर से भी चालू होगा रावघाट से भी चालू होगा। और, उसके डीपीआर में (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) हर प्रकार की जानकारी है कि लाइन में कितने ब्रिज होंगे, स्टेशन कितने होंगे, सुविधाएं क्या-क्या होगी, उसके लिए खर्च किस प्रकार से होंगे। इसकी पूरी जानकारी जुलाई में तैयार हो जाएगी और उसके बाद तुरंत काम होगा।

श्री पांडेय ने कहा कि यह सभी बस्तर वासियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कनेक्टिविटी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और अर्थव्यवस्था में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हो चुका है। गरीब भी रेलवे में यात्रा सहजता से करेगा। वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी। ऑन डिमांड सीट मिलेगी। सिंगल लाइन थी वहां डबल लाइन किया गया है जहां डबल लाइन था वहां ट्रिपल लाइन किया गया है। हाई स्पीड ट्रेन अपनी गति के साथ दौड़ सके, निश्चित समय में पहुंच सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है।

रावघाट परियोजना के साथ-साथ एक अन्य सौगात पुरानी रेलवे लाइन जो धमतरी से लेकर कोंडागांव तक था जिसे द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उखाड़ दिया गया था इस लाइन में ब्राडगेज के लिए सर्वे के लिए आदेश दिया है। उसमें सर्वे होगा और भविष्य में भी उसमें भी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इससे केवल यात्रियों को ही नहीं खनिज संसाधनों के भी यातायात में सुविधा होगा।

सांसद श्री पांडेय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा की है जिसका उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया है। यह बजरंग दल, राष्ट्रवादी संगठन और देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इसकी व्यापक आलोचना हुई है। पूरे देश में गुस्सा है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जो वादा किया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जब इस देश के अंदर कांग्रेस को लगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट प्राप्त करना है तब तक बहुसंख्यक हितों को नजरअंदाज किया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस विधायकों का परफॉर्मेंस पुअर, चुनाव में कर्मों का फल मिलेगा-नोबेल वर्मा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा ने कहा कि अगर पार्टी में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल नहीं तो नोबेल वर्मा सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी पार्टी के साथ नही रहेंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे से नाराज होकर उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की प्रदेश इकाई के तमाम विंग के सभी पदाधिकारियों के साथ अपने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रारंभिक मेंबर जरूर बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उन्होंने कहा की 15 साल की भाजपा सरकार की ही तरह कांग्रेस की साढ़े 4 साल की सरकार का भी हाल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। श्री वर्मा ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि आगामी दिनों में एनसीपी का भी विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने इस बात को झारखंड से जोड़ा। बिलासपुर जिले के संभावित प्रत्याशियों के साथ पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता होगा या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने नाराजगी कांग्रेस पर जमकर निकाली।

तीन साल बीतने पर भी अच्छे वित्त मंत्री ने छात्रवृत्ति अब तक क्यों नहीं दी?-भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं को एक अच्छा वित्त मंत्री बताते हैं तो उन्हें प्रदेश को यह भी बताना चाहिए कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की राशि क्यों दबा ली गई है? श्री ठाकुर ने इस बात पर अफ़सोस जताया है कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के मेधावी छात्रों को मेधावी छात्र योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जो छात्रवृत्ति मिलनी थी, वह अभी तक नहीं मिली है। श्री ठाकुर ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वज़ह पूछते हुए यह भी सवाल दाग़ा है कि %एक अच्छे वित्त मंत्री% का वित्तीय मैनेजमेंट कैसे फेल हुआ? भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि जब तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार परेशान हो रहे हैं और अपने हक़ के पैसों के लिए दर-दर भटकने को मज़बूर हैं तो प्रदेश की जनता इस बात पर कैसे भरोसा करे कि मुख्यमंत्री बघेल एक अच्छे वित्त मंत्री हैं? श्री ठाकुर ने सवाल किया कि आख़िर मेधावी छात्रों की यह राशि क्या प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जमा करके रखी है? या फिर, क्या यह राशि भी 'छत्तीसगढ़ एटीएम' के ज़रिए कांग्रेस की तिज़ोरी में चली गई? प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को इन सवालों का ज़वाब चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा प्रदेश सरकार को नहीं देना है। बल्कि यह तेंदूपत्ता संग्राहकों के लाभांश का पैसा है, जिसे प्रदेश सरकार दबाए बैठी है।

हनुमान चालीसा पाठ करने से भाजपा नेताओं के नफ्रत के भाव का नाश होगा- मोहन

रायपुर। भाजपा नेताओं के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भाजपा नेताओं के मन मस्तिष्क में बैठी वैमनस्यता नफ्रत और कटुता के भाव का नाश होगा सद्बुद्धि आएगी और आम जनता की मूल समस्या बढ़ती महंगाई बेरोजगारी देश में गिरती अर्थव्यवस्था बिकती सरकारी कंपनियां रसोई गैस के बढ़ते दाम पेट्रोल डीजल की महंगाई जैसे विषयों पर चर्चा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। भाजपा और बजरंग दल की बजरंगबली भक्ति दिखावा मात्र है जब प्रतिबंध की बात आ रही तब हनुमान चालिसा के पाठ का ढोंग कर रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अभी वर्तमान में कहीं भी बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा है स्थिति और परिस्थिति के अनुसार प्रतिबंध लगाने की बातें कही गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहिए, कि कर्नाटक और गोवा में भाजपा की सरकारों ने राम सेना पर बैन क्यों लगाया था? जो भाजपा जय राम का नारा लगाती है राम जी के नाम से वोट लेती है चंदा लेती है और सत्ता हासिल की थी।

भाजपा के षडयंत्रो के कारण आरक्षित वर्ग को हो रहा नुकसान - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने 76 प्रतिशत आरक्षण बिल को राजभवन के पीछे छिप कर रोकने का षड्यंत्र किया है। जिसका नुकसान भर्ती प्रक्रिया में जनसँख्या के अनुपात में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नही मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण के लाभ से पूरी तरह वंचित हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जनसँख्या के अनुपात में आदिवासी वर्ग को 32 प्रतिशत एससी वर्ग को 13 प्रतिशत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वालों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण सदन में पारित किया था। जो लगभग 5 माह से हस्ताक्षर नही होने के चलते राजभवन में अटकी हुई है। जिसके चलते सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया और स्कूल कॉलेज में एडमिशन में ओबीसी वर्ग को 13 प्रतिशत एससी वर्ग को 1 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वाले को 4 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा हमेशा से आरक्षित वर्ग के खिलाफरही है। भाजपा पूंजीपतियों के समर्थक और गरीब एवं दबे कुचले लोगों की विरोधी है। भाजपा नहीं चाहती कि दबे कुचले शोषित वर्ग समाज के मुख्यधारा में जुड़े और खुशहाली के साथ जीवन यापन करें आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने कई दफ्ा सार्वजनिक मंचों के माध्यम से देश में आरक्षण को खत्म करने की वकालत कर चुके हैं।

कांग्रेस नेता भी सुरक्षित नहीं आम जनता कैसे होगी - मूणत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेशभर में कानून-व्यवस्था को लगातार मिल रही चुनौती को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। श्री मूणत ने कहा कि जब राजधानी में ही गुंडे-बदमाश सरेराह अपराधों को अंजाम दे रहे हों और प्रदेश सरकार व उसकी पुलिस हाथ-पर-हाथ धरे बैठी हो तो प्रदेश के अन्य हिस्सों का तो भगवान ही मालिक है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्री मूणत ने बुधवार की रात राजधानी के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दो हिस्ट्रीशीटर बदमाशों द्वारा सरेराह एक कांग्रेस नेता के विवाह समारोह से अपनी पत्नी, भतीजों व अन्य परिजनों के साथ लौट रहे थे, की कार पर लाठी से हमला और ठाकुर पर चाकू से वार करके लूट की कोशिश बताती है कि प्रदेश में अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है और प्रदेश सरकार और पुलिस कितनी लाचार हो गई है! श्री मूणत ने कहा कि राजधानी में सुपारी किलिंग से लेकर लूटपाट, चाकूबाजी, मारपीट, हत्या की कोशिश और हत्याओं की वारदातें इस तेजी से बढ़ रही हैं कि प्रदेश की राजधानी तक में आम लोगों की सुरक्षा दाँव पर लग गई है और लोगों का घर से निकलना और सुरक्षित वापस घर पहुंचना मुश्किल हो गया है।

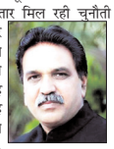

बेमौसम बरसात में फसल बर्बाद, संवेदनहीन है सरकार - चंदेल

■ किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेमौसम बरसात में छत्तीसगढ़ के किसानों की फसल बर्बाद होने के बावजूद उन्हें कोई सहायता न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि असमय आंधी और बरसात के कारण प्रदेश के किसानों की रबी फसल, सब्जी व फल की फसल बर्बाद हुई है। अकेले जांजगीर चांपा जिले में 25 हजार एकड़ वह

पूरे प्रदेश में लाखो एकड़ में फसल बर्बादी की कगार पर बताई जा रही है। पूरे प्रदेश में असमय वर्षा से फसल चौपट हुई है। इससे राज्य के किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान कर्ज के दलदल में फंस रहा है। परंतु संवेदनहीन भूपेश बघेल सरकार ने नुकसान के सर्वे हेतु अभी पहल भी प्रारंभ नहीं की है। यह दुर्भाग्य जनक है कि प्रदेश के किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है लेकिन सरकार, उसके कृषि और राजस्व विभाग ने अब तक नुकसान का सर्वे शुरू नहीं किया है। इससे सरकार की मंशा साफ नजर आ रहा है कि वह किसानों को उनके हाल पर छोड़कर बैठी है। सरकार राज्य के किसानों के नुकसान की भरपाई करने का इरादा नहीं रखती। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि पिछले साल भी किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी देर से आरंभ होने पर बिना बिके भीग गई थी। भीगी हुई धान खरीदी नहीं की गई और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। इस बार भाजपा के दबाव में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू तो की गई लेकिन कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। अब किसानों ने फिर से धान बोई थी, फल सब्जी की फसल भी लगाई थी, जो असमय बारिश और अंधड़ में चौपट हो गई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीगर राज्य में 50 50 लाख का मुआवजा देने खड़े रहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति उनकी संवेदना नहीं जागती।

'आकार-2023'- युवा, बच्चे और बुजुर्ग ले रहे शिल्प कलाओं का प्रशिक्षण

■ संस्कृति विभाग द्वारा महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में दिया जा रहा है प्रशिक्षण

रायपुर। संस्कृति विभाग द्वारा महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में दिया जा रहा है प्रशिक्षणसंस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक कलाओं पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर आकार-2023 में युवा, बच्चे और बुजुर्ग उत्साह के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं

संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक कलाओं पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर आकार-2023 में युवा, बच्चे और बुजुर्ग उत्साह के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। गौरतलब है कि संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण, प्रचार-प्रसार, जागरूकता तथा लोगों में इनके प्रति रूचि जागृत करने के

लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 'पारंपरिक शिल्प एवं विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार-2023' का आयोजन रायपुर के सिविल लाइन स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में 01 मई से शुरू हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 मई तक चलेगा।

संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 'आकार-2023' में पंजीकृत प्रतिभागियों को म्यूरल आर्ट, पेपरमेसी, क्ले आर्ट, काष्ठ, बांस शिल्प एवं मूर्तिकला, चित्रकला, मधुबनी आर्ट, पटचित्र, धान ज्वेलरी, ड्राई फ्लावर, ग्लास पेंटिंग, गोदना आर्ट, पैरा आर्ट, टेराकोटा, रजवार भित्ती, क्लासिकल नृत्य, नाटक, फोक डांस, जूट शिल्प, मेहंदी आर्ट, गोबर आर्ट, वारली आर्ट, पिछवाई आर्ट, सेंड आर्ट, मंडला आर्ट, मांदना आर्ट, गोंड आर्ट, सौरा आर्ट, स्केच पेंटिंग, केनवास पेंटिंग, बोनसाई आर्ट, वाद्य-यंत्र प्रशिक्षण एवं मेकिंग विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद समापन के दिन प्रशिक्षुओं द्वारा निर्मित कलाकृतियों एवं समानों को परिसर में प्रदर्शित करने के साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.